provocative and partisan attitude adopted by the Pakistan High Commission this year in denying visas to over 1,000 of the 3,000 intending pilgrime to visit Nankana Sahib and Panja Sahib, two of the holiest shrines of the Sikhs, in particular, and the Hindus, in general. Not only Sikhs, but a large number of non-Sikhs too used to visit these shrines, every year—since the Shimla Accord was signed in 1974—in April, for about ten days, on the eve of Baisakhi.

This year, however, the Pakistan High Commission adopted a highly provocatiive and partisan attitude by not granting visas to the intending pilgrims. Out of around 3,000 intending pilgrims, over 1,000 were denied visas, which included children too. The women were granted visas, refusing permission to their husbands, to embarrass them as they would have to go alone, unaccompanied by their husbands and children. While no reasons were generally assigned for refusing visas to these pilgrims, the non-Sikhs or Sehajdari Sikhs were refused visas saying that Hindus have no place in Pakistan. Evidently, it was highly provocative and reflected an effort to divide the pilgrims on communal lines and hurt their religious sentiments.

I believe the Ministry of External Affairs might have taken up the issue with Pakistan. The hon. Minister may like to apprise the House of the outcome thereof.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी की ओर से जो कुछ शिन्दे साहब ने कहा है उससे पूरी तरह से सहमति प्रकट करता हूं और एसोशिएट करता हूं। यह पहला उदाहरण नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार वहां पर जिन्हें गैर मुसलमान वह मानते हैं, जिसमें उनका एक तबका खुद भी शामिल है, उनसे जितना भेदभाव कर रहे हैं वह अत्यन्त चिंताजनक है। खास तौर से यह बात है कि हम यहां रहने वाले भारतीयों जिनके तीर्थ स्थान सिखों के, हिन्दुओं के भी वहां हैं, उनको वहां न जाने दिया जाये। यह तो बाई-लिटरल रिलेशनशिप के विरुद्ध है। सारा सदन मेरे और शिन्दे साहब के साथ सहमत होगा कि बहुत ही उच्च स्तर पर इस विषय को सरकार को पाकिस्तान के साथ लेना चाहिये, जिससे आगे किसी प्रकार की बाधा न डाली जाये और जो सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय नियम है, उनके अनुसार ऐसे लोगों को जो-जो सुविधायें दी जाती है, वही सुविधायें हिन्दुओं को, सिखों को वहां पर दी जानी चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि सारा सदन इससे सहमत होगा।

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Jagdish Prasad Mathur to continue his speech.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : यों तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बहस का आनन्द ही किरकिरा हो गया। जिस प्रकार से कुछ व्यवस्था हुई और कुछ आवश्यकतायें पूरी करनी पड़ीं उनके कारण राष्ट्रपति जी के भाषण पर बहस एक प्रकार से बेमानी हो गई है। फिर भी कुछ तो कहना होगा। राष्ट्रपति जी के भाषण पर टिप्पणी करते हुये जो कुछ भी मेरी टिप्पणियां होंगी, सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ तो हो ही नहीं सकतीं, वह सरकार के प्रति होंगी। यद्यपि कहा यह जाता है कि यह राष्ट्रपति का भाषण है, लेकिन वह राष्ट्रपति का भाषण नहीं होगा, वह तो सरकार का ही भाषण होता है। यों तो इंगलैंड में कहा जाता है, राजा या महारानी कहती थी "माई गवर्नमेंट" तो राष्ट्रपति भी कहते हैं "माई गवर्नमेंट" लेकिन संविधान का जो बंधन है, उसमें "माई गवर्नमेंट" तो नहीं होता, हमारे राष्ट्रपति हैं, यही कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यदि राष्ट्रपति

महोदय स्वतंत्र होते अपने मन की बात कहने में, तो शायद जो कुछ इस भाषण में लिखा गया है, उस सब को नकार कर कुछ दूसरी बात ही कहते ।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : लेकिन यह तो बहुत खराब बात है कि हमारे राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, यह मत कहिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : संविधान की दृष्टि से मैंने कहा ।

श्री चतुरानन मिश्र : आपने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रपति स्वतंत्र होते ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप अपनी बात कह दें ।...(**व्यवधान**) .. देखिये मिश्र जी, मैं समझता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री चतुरानन मिश्र : हम मीठी चुटकी लेते हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मीठी चुटकी में तो ज्यादा मजा होता है । ...(**व्यवधान**)... तकलीफ क्या है, कोई परेशानी नहीं है । मैं कहूंगा कि आगे भी लेते रहिये, कुछ मजा तो रहे ।

श्री चतुरानन मिश्र : आगे बढ़िये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि यदि राष्ट्रपति जी अपनी बात कहने में स्वतंत्र होते, संविधान के बंधन उन पर न होते तो शायद जितने यहां पर क्लेम किये गये हैं, जितने दावे किये गये हैं और जितनी बात कही गई है, सबको नकार कर संभवतः कुछ उलटा ही कहते । मैं बाकी विषयों पर देर में आउंगा । एक बात पर मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं कि किस प्रकार से सरकार ने उनको ही फंसा दिया । यहां पर कहा गया "Government is concerned about the increase in prices.", और आगे भाषण में कहते हैं कि प्राइसेज हमने कंट्रोल कर ली है । अब ये इस प्रकार का अन्तर्विरोध राष्ट्रपति के शपथ भाषण में सरकार कर दे तो इससे ज्यादा विडम्बना क्या हो सकती है? मेरा निवेदन यह है कि काश कोई ऐसा होता कि राष्ट्रपति जी सरकार की बात तो कहते लेकिन कहते-कहते यह भी संवैधानिक स्वतंत्रता होती कि वे अपनी बात भी कह सकते तो शायद कुछ प्रेरणा मिलती सारे देश को, सारे संसार को एक दिशा मिलती । लेकिन इस भाषण में न कोई दिशा है, न कोई निर्देश है, निसत्व है जिसको कहते हैं बेमानी । एक कैटेलॉग मात्र है चीजों का । मेरे दो साथी सरकार की ओर से बोले, मुझे खेद है कि वे यहां पर नहीं हैं ।

SHRI JAGESH DESAI: I want to know whether the word bemani can be used. Is it parliamentary?

श्री संघप्रिय गौतम : बेमानी, जिसके माने नहीं है ।

SHRI SATISH AGARWAL: Meaningless!

SHRI JAGESH DESAI: No objection!

एक माननीय सदस्य : डबल मीनिंग नहीं है..(**व्यवधान**)..बेईमानी नहीं है । ...(**व्यवधान**)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बेईमानी नहीं है । बेमानी, निरर्थक, जिसका अर्थ नहीं है ।

SHRI JAGESH DESAI: I have understood it. No objection.

श्री सतीश अग्रवाल : जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जी नहीं, मूरत देखी अपनी जैसी । अपनी सूरत आपने बेईमानी शब्द के साथ जोड़ दी, भइया, मुझे बड़ा अफसोस है सरकार वालों पर, श्रीमान, आप बड़े विद्वान है, योग्य है, मंत्री रहे है, तो कम से कम बेमानी और बेईमानी में अंतर तो

करते लेकिन आपने . . . (व्यवधान) . . . आपने अपने दिल की बात को समझ लिया . . . (व्यवधान) . . .

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : माथुर साहब, आप मुद्दे पर आइए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उनकी बात यही थी । अपने पचौरी जी बोले थे । उनको क्या कहूं क्योंकि कुछ बोले ही नहीं । बोले संघ ऐसा है फलां जैसा है । मालूम होता है क्या कहूं, हल्की सी बात है, कुछ शब्द बदल कर कह देता हूं । शब्द अगर वही रख दिये तो मुमकिन है गड़बड़ हो जाये । बिहार में एक कहावत है भाई हो, शब्द बदल रहा है, कुर्ता एक, हेराफेरी कचहरी जाये और तो कुछ है नहीं बोलने के लिये तो लिहाजा जब कुछ बोलना होता है, हेराफेरी करो वहीं संघ पर, आक्रमण आर०एस०एस०, बी०जे०पी० पर पचौरी जी करते रहे । कुर्ते की जगह कुछ और शब्द बोला जाता है, वह मैं बोलना नहीं चाहता । और जहां तक जयन्ती नटराजन जी का सवाल है, उन्होंने बहुत ही योग्यता के साथ एक ऐसे मुकदमे की पैरवी की है जिसमें कोई दम नहीं है । उनका मूल अभिप्राय यह था कि सरकार ने जो नई नीतियां अपनाई है, उनके कारण बहुत प्रगति हुई है और मानो एक स्वर्ग आकाश से उतरकर आने वाला है । सच्चाई इसके उलट है । यह आपने जो प्रकाशित किया है इकोनोमिक सर्वे उसी को आपके सामने रखूंगा जिस से पता लगेगा कि असली तस्वीर क्या है । कहावत है उर्दू में–मियां की जूती मियां के सिर । उन्होंने बहुत जोर से कहा कि बड़ी तरक्की हुई है और बहुत अच्छा काम हुआ । मेरे मित्र बैठे हुये है सतीश जी . . . .

श्री चतुरानन मिश्र : यह आपको यूज नहीं करना चाहिये किसी जाति के बारे में । यह जो फरेज है इसको हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । हिन्दू की जूती हिन्दू के सिर ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह तो कहावत है ।

श्री चतुरानन मिश्र : हमें और आपको यह इस्तेमाल नहीं करना चाहिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मुझे यह अंदाज नहीं था कि आप इतने फंडामेंटलिस्ट हैं कि जहां हमने मियां कहा आप मुसलमान समझ लेते हैं । मियां का मतलब हजरत, या श्रीमान होता है । मियां बहुत ही इज्जतदार शब्द है उर्दू में यह आप जानते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : इसलिए यह कह रहे हैं इज्जतदार है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह कहावत है । मियां का मतलब श्रीमान होता है । अगर आपको पसन्द नहीं है तो आपके लिये कह देता हूं श्रीमान की चप्पल श्रीमान के सिर ।

उपसभाध्यक्ष (कु० सरोज खापर्डे) : आप डायरेक्ट बात मत करिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो आप कहलवाना चाहते है वह मैं मैडम के माध्यम से कहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप इधर देख कर बोलिये, उधर देखकर मत बोलिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मुझे मालूम नहीं था आप तशरीफ रखती हैं वरना मैं आपकी तरफ देखता ही रहता । आप आग्रह कर रही हैं तो आपकी तरफ ही देखूंगा । वायदा करता हूं दूसरी तरफ नहीं देखूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप मियां से उतरे और . . .

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था कोई समय नहीं लूंगा । अगर आज से आपको मियां माथुर कह दें तो बुरा तो नहीं मानेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मुझे कोई एतराज नहीं है । बल्कि मेरे दोस्त मुझे

कहते हैं – मियां क्या हो रहा है । अगर नीचे नजर डालेंगे तो मेरा पायजामा तो मियां वाला ही है ।

मैं अर्ज कर रहा था कि आपके इकोनोमिक सर्वे में क्या कहा गया है । यह आपको साबित कर देगा कि कितनी तरक्की हुई है । मैं कह रहा था कि मेरे मित्र सतीश जी ने पिछले सत्र के दौरान एक सवाल किया था । उन्होंने दिखाया था कि किस प्रकार से प्रगति हुई है । सेविंग के बारे में विस्तार से बताया था । मैं उसी बात से शुरू करता हूं । यह आपका ही जो इकोनोमिक सर्वे है इसका चार्ट एस-8 सेविंग के बारे में है । 1992-93-94 अगर कहीं बढ़ोतरी हुई है तो केवल प्राइवेट सेक्टर में । पब्लिक सेक्टर में 90-91 में टोटल 23.7 परसेंट और अगले साल टोटल 23.1 परसेंट हुई है । प्राइवेट सेक्टर के अन्दर वह भी हाऊस होल्ड सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है और दूसरे कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई । नटराजन जी नहीं बैठी हैं उन्होंने पता नहीं कैसे कह दिया तरक्की हुई है । अब जी.डी.पी. को लीजिये । मेरे साथी जो बैठे हुए है उनके लिये आसान कर देता हूं । टेबल II है इसमें 15.57 परसेंट है और आगे 30.7 परसेंट है । यह भी फाइनल नहीं है और 94-95 का दिया ही नहीं है ।

इन्फलेशन का उल्लेख पेज 72 पर है । इसके बारे में इकोनोमिक सर्वे क्या कहता है ।

"The annual inflation rate for primary articles as on 4 February 1995 was 15.4 per cent compared to 8.7 per cent on the corresponding date in 1994."

कितना इन्फलेशन हो गया 8.7 से 15.4 परसेंट । इसमें और महत्व की बात है ।

"Food articles, which account for over half the weight of the primary articles group, recorded a rise of 13.7 per cent contributing over 23 per cent of this year's annual inflation."

वह भी किन चीजों का रेट बढ़ा ? प्राइमरी चीजें हैं । रोटी-रोजी, जो खाने की चीजें हैं । आपको अन्दाजा नहीं है कि गरीब की हालत क्या हो रही है ?

"चन्द आहें, चन्द आंसू,
चन्द हल्की सिसकियां,
जिन्दगी और जिन्दगी का
साजो समां देख लो ।"

आप गरीब की झोंपड़ी में जाकर देखिए कि क्या हालत है । जैसा मैंने कहा कि चन्द आहें, चन्द आंसू, चन्द हल्की सिसिकियां । जिन्दगी और जिन्दगी का साजो-समां देख लो । मिडिल क्लास क्या कहता है ? शेर याद आ गया है "हम नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, मगर आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद ।" यह मिडिल क्लास की हालत है । अगर आप देखें तो आपका फूड स्टाक और तमाम सारी चीजें बढ़ रही हैं । मैं मानता हूं कि फूड स्टाक भरा पड़ा है, लेकिन उसका फायदा क्या है ? क्या आपने देखा है कि गल्ला मौजूद है, लेकिन वह खराब हो रहा है । गल्ला आपने पैदा किया लेकिन आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है । गरीब के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है । मैं साबित करता हूं । यह आपका एकानामिक सर्वे है, अलोकेशन कितना हुआ है, 91.6 परसेंट, 1991 में और आफ-टेक कितना है 12.8 में हर साल के आंकड़े नहीं पढ़ता । अन्त में कहता हूं, 9.9 मिलियन स्टाक में से आफ टेक कितना है, 5.86 । इसका मतलब है कि आपके पास माल है, लेकिन दुकानदार उठाता नहीं है, क्योंकि खरीदार के पास खाने के लिये पैसा नहीं है ।

This is the situation.

आप कहते हैं कि खाने के लिए है । आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहां इतना गल्ला पैदा हुआ है । उस गल्ले को, अनाज को पैदा करके कोई क्या करेगा, जो किसी भूखे की ओठों तक नहीं पहुंच सकता है । अगर वह खाना लोगों के ओठों तक नहीं पहुंच सकता है और केवल किसी गांव के गोदाम में, या आपके

किसी गोदाम में सड़ रहा है, जो पी०डी० एस० की दुकानों में सड़ा हुआ पहुंचता है— आपको याद होगा, नटराजन जी, आपकी रूलिंग पार्टी के एक सांसद ने कहा है कि पी०सी०एस० काम नहीं कर रहे हैं? क्यों? यह किसकी जिम्मेदारी है? यह सेंट्रल गवर्नमेंन्ट की जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है।

मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। कैपिटल फार्मेशन के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि:

Capital Formation. Page 130, paragraph 67:

"Gross investment in real terms (at 1980-81 prices) in agriculture has stagnated. It was Rs. 4636 crores in 1980-81 and Rs. 4617 crore in 1992-93 (actual). From 18 per cent of the total gross domestic capital formation in 1980-81, it has declined to 9 per cent in 1992-93. The decline in real capltal formation in agriculture by the public sector is more perceptible, as it has come down to Rs. 1065 crore in 1992-93 compared to Rs. 1796 crore in 1980-81."

यह आपका कैपिटल फार्मेशन है, और वह भी एग्रीकल्चर सैक्टर में सबसे कम है। इसके बाद भी आप कहते है कि गांवों में खुशहाली आएगी।

Who is responsible for this?

आगे आइए। जो कोर सैक्टर है कोल। कोयला देख लीजिए। पेज 136 में रिमार्क है, पैरा 11:

"As on December 31, 1994, out of 71 projects under implementation in the coal sector, 22 projects are bedevilled by time and cost over-runs. On an average, the cost overrun per project is about Rs. 77 crore and the time overrun per project is about 38 months."

कोल आपके पास है, नहीं, पैट्रोलियम सेम थिंग। विचित्र बात है कि यह सारा देखने के बाद, आपके ही इन डाक्युमेंट्स के बाद आप यह दावा करें कि तरक्की हुई, गरीबी हटी है, महंगाई घटी है, यह सिवाय आप कर सकते हैं, टी०वी० के ऊपर प्रचार। पिछले दो-तीन दिनों से हम देख रहे हैं कि टी०वी० पर प्रचार हो रहा है कि इन्फलेक्शन सिंगल डिजिट हो गया है, कितना? 9.98 हो गया है। से घट कर 9.98 आ गया। आप जानते थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में बहस होने वाली है, इसलिये झूठा प्रचार किया जा रहा है, लोगों को धोखा देने के लिये। सब से बड़ी बात यह है कि आप परसेंटेज बढ़ा लें, परसेंटेज घटा लें, लेकिन उससे आम आदमी का कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वह तो यह चाहता है कि बताइये गेहूं का भाव घटा है क्या, क्या चावल का भाव घटा है, क्या कपड़ा मुझ को सस्ता मिलेगा, क्या मुझे खाद सस्ती मिलेगी? मुझे डर है कि आने वाले दिनों में पैट्रोल की कीमत आप बढ़ाने वाले हैं। क्यों बढ़ाने वाले हैं, जबकि दुनियां का बाजार घट रहा है? क्योंकि आपका जो तरीका है वह यह है कि सेंट्रल पल गवर्नमेंट का बनता है, पैट्रोल के बारे में। जब उसमें कमी होती है तो आप कीमतें बढ़ा देते हैं। इसका सबूत है कि इराक के बारे में समय सेस लगाया आपने लगाया था और यह साफ तौर पर कहा था, मंत्रिमंडल के लोगों ने यह कहा था कि यह जो सेस लगा रहे हैं, यह जब तक इराक का युद्ध रहेगा, जब तब तक रहेगा, जिस दिन युद्ध बन्द हो जायेगा, उस दिन यह सेस हटा दिया जाएगा। युद्ध कई वर्ष पहले बन्द हो चुका है, लेकिन सेस आपने नहीं हटाया है। एक बार पैट्रोल की कीमतें बढ़ जायें, तो कम नहीं की जाती हैं। सतीश शर्मा जी होते, तो सुन लेते। पैट्रोल की कीमतें बढ़ायेंगे, तो नेचुरली जितनी भी चीजें हैं, सबकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, सब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यह सारा दृश्य देखने के बाद आप भले ही संतोष कर लें, अपनी डुगडुगी बजा लें, लेकिन दुनियां आपको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन यह है, हमारे सदन के नेता माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, आप जरा गिरेबान में मुह डाल कर

देखिए, झूठा प्रचार मत कीजिये। आप टी०वी० पर यह कह रहे हैं कि 9.98 इनफ्लेशन का रेट आ गया है, लेकिन इनफ्लेशन कम नहीं हुआ है। इनफ्लेशन का रेट घट गया है। इस तरह का झूठा प्रचार करने के बजाय आप सच्चे तौर से कुछ सेवा करने का प्रयत्न करें, तो बहुत अच्छा होगा। एक बात और है। ईमानदारी भी नहीं है, यह बिजनेस स्टेंडर्ड है, इसमें कहा गया है, यह आपके स्वयं के सी० एस० ओ० की ही फिगर्ज थीं।

"Unhappy with these figures, the Finance Ministry withheld the release of quick estimates for a month. Dr. Manmohan Singh questioned the methodology."

यह कर रहे हैं आप। जो उन्होंने फिगर्ज दिये हैं सी० एस० ओ० जो गवनमेंट का आर्गेनाइजेशन है, उसने जो फिगर्ज छापनी चाहीं, डा० मनमोहन सिंह का आदेश जाता है कि यह फिगर्स प्रकाशित नहीं की जाएं। वह कहते हैं कि मैथोडॉलोजी गलत है। यह मेथोडॉलोजी गलत थी तो पहले भी गलत थी लेकिन जब आपको ठीक लगा तो आपने फिगर्ज मान ली। अब आपको लगता है फिगर्ज गलत हैं, आपको पसंद नहीं आई तो आप गलत बताते हैं। यह आपकी ईमानदारी है? डा० मनमोहन सिंह होते तो मैं पूछता कि यह जो कमेंट हैं बिजनेस स्टेंडर्ड के समाचार पत्र का है, क्या यह गलत है। अगर गलत है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत नहीं है। सच्चाई को दबाया जा रहा है।

दूसरा आपका यह दावा है कि बड़ी शान्ति है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हुए। कौन कहता है झगड़े नहीं हुए हजूर? हुए हैं लेकिन जिस पैमाने पर आप चाहते थे वैसे नहीं हुए। क्या बम्बई में बम कांड नहीं हुआ केवल हफ्ता-पंद्रह दिन पहले दिल्ली में हो जाता, अगर पकड़े नहीं जाते। कलकत्ता के अन्दर बम कांड हुआ होता मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि सी०बी०आई० ने यह रिपोर्ट दी है कि महाराष्ट्र के पिछले मुख्य मंत्री महोदय के संबंध अंडरवर्ल्ड से थे। उस रिपोर्ट में लिखा है डेटवाइज कितना रुपया, किस किस दिन किस किस अंडरवर्ल्ड के आदमी से दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं। आप सी० बी० आई० की रिपोर्ट देख लीजिए।

I challenge. It is on record. We have got our sources".

आप कह रहे हैं शांति बनी रही है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या हिन्दू मुसलमान झगड़ा ही झगड़ा होता है। क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर आपने कभी देखा है कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं? तमाम महिलाएं पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं। क्या आपने देखा है कितने मर्डर हुए हैं? क्या आपने देखा है कितनी बार गोली चलाई गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे मुलायम सिंह की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं क्योंकि आपके स्पोर्ट से वे जिंदा हैं। कौन नहीं जानता कि 2 फरवरी के दिन मुजफ्फरनगर के पास क्या हुआ। पहाड़ के लोग डिमोस्ट्रेशन करने आ रहे थे। सारी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। ये जितने सवालात हैं ये चीजें अगर खोलकर रख दें तो आपमें से एक एक आंसू बहाने पर मजबूर न हो जाएं तो मेरा नाम नहीं। महिलाओं पर अत्याचार किया गया। लाठियां चलायी गयीं। सी०बी०आई० की रिपोर्ट है पटना हाईकोर्ट के पास। उन अफसरों ने क्या किया। अफसरों ने जालसाजी की। अफसरों ने रिकार्ड बदले एण्ड यू डिड नथिंग। ये आई० पी०एस० आफिसर्स और आई०ए०एस० आफिसर्स किसके अधीन हैं? केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं तो किसके अधीन हैं। यू आर रिस्पांसिबिल। जो आपके होम मिनिस्टर हैं, ये जिम्मेदार हैं। सी०बी०आई० की रिपोर्ट आने के बाद आप चुप बैठे हैं। एक भी आपने अफसर का तबादला नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है उन लोगों को उठाकर कठघरे में बंद किया जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं शांति है।

SHRI VAYALAR RAVI: How can we do it?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You can do it. You can ask the Government of U.P. to do it.

आप कह सकते हैं । और बहुत सी चीजें हैं । आई०पी०एस०, आई०ए० एस० आफिसर्स को आप हटा नहीं सकते ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : माथुर साहब जरा बैठिए एक मिनट ।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : "होम मिनिस्टर ने क्या कहा", वह मैंने सुना नहीं ठीक से, जरा बताइए क्या कहा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने यह अर्ज किया कि सी०बी० आई० की रिकोर्ड आने के बाद जो मुजफ्फरनगर के पास हुआ उसमें एक भी आई०पी०एस० और आई० ए० एस० अफसर---जिनके नाम हैं, जो जिम्मेदार हैं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई उत्तरा खंड के मामले में ।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसकी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट पर आती है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जी हां मूलतः आती है । लेकिन आपके आदेश से---उनका कहना है--पुलिस ने वहां रोका था । आपको स्मरण दिला दूं । आपकी बैठक में, जो आपने यू०पी० के नेताओं की बैठक बुलायी थी वहां पर यह सवाल खड़ा किया गया था और वहां पर यह आया कि आपके आदेश से हुआ है । इसलिए आपकी जिम्मेवारी है । दूसरा क्या आपकी जिम्मेदारी, केन्द्र सरकार की... **(व्यवधान)**

SHRI VAYALAR RAVI: Mr. Mathur. ...*(Interruptions)*.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ठीक है आप बैठिए । आपको होममिनिस्टर बन जाने दीजिए । आप होम मिनिस्टर बन जाइए । क्या उत्तर प्रदेश सरकार आपके सहारे से नहीं चल रही है । आप जिस दिन चाहें उस दिन मुख्य मंत्री को ठीक कर सकते हैं । आप नहीं चाहते । कल ही का उदाहरण है । गृह मंत्री महोदय उत्तर देने को खड़े हुए, जनेश्वर मिश्र जी खड़े हो गए, तो उनको लगा कि अब नहीं बोलना चाहिए । नहीं बोले । क्यों ? मुलायम सिंह कुछ कह देंगे । तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है बिहार के अंदर क्या हुआ जिम्मेदारी आपकी है । वहां की कैबिनेट के एक मंत्री राहीजी हैं । वहां के मंत्री धरने पर बैठते हैं । आपको हालात मालूम हैं और आपके कान पर जूं नहीं रेंगती । आप चुपचाप सुनते रहते हैं । महीनों और वर्षों से लालू प्रसाद की सरकार क्या नहीं कर रही है । आप चुप बैठ हैं क्योंकि आपको चाहिए अगली लोकसभा के चुनाव के अंदर उनका समर्थन..... **(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव : क्या क्या बोल रहे हैं आप ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हां, मैं ठीक बोल रहा हूं । आपका नम्बर आएगा तो बोलिएगा ... **(व्यवधान)**

जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है जो कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है। आपने हमारी चार सरकारों को बहाने से गिरा दिया । जहां पर एक बाल बांका नहीं हुआ था उस हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिसमिस कर दिया था । आज वहां पर अत्याचार के खुले आम हजारों केसेज हो रहे हैं और आप शांति से बैठे रहते हैं । कहते हैं दुनियां में कुछ नहीं हो रहा है, अमन और शांति है । आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहलवाया है । लेकिन बहुत ही सादे शब्दों में कहता हूं, यह मिथ्या है, असत्य है । सत्य से आंख मूंदकर शतुरमुर्ग नहीं बचता, आप भी नहीं बचेंगे, यह मेरा विनम्र निवेदन है ।

और देखिए, मुजफ्फरनगर में सी० बी० आई० की मैंने बात की है । इनफिल्ट्रेशन के बारे में कहीं जिक्र नहीं है । राष्ट्रपति जी के भाषण में पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है । कहा गया है, हमने फलाना समझौता कर लिया है । किससे समझौता किया है वहां ? कुछ आतंकवादियों से । आज ही एक सवाल था कि वहां के एक प्रदेश के मुख्य मंत्री, वहां जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ समझौता कर रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं । दिस इज योर वे । इनफिल्ट्रेशन के बारे में आपने क्या

किया ? उससे भी समझौता कर लिया है । क्यों समझौता किया है ? यह समझौता इनफिल्ट्रेशन के बारे में आज का नहीं है जिस दिन से हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार आयी है उस दिन से है । आज लगभग एक करोड़ बंगलादेशी इनफिल्ट्रेटर हैं । मैं खुल्लमखुला कहना चाहता हूं चाहे आप मुझे सांप्रदायिक कहें जो वहां से डर से भाग करके हिंदू आया है . . . (व्यवधान)

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Last time, you said that this was two crores. How could it come down to one crore in ten days?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: One crore was sent to Bengal. (*Interruptions*).

DR. BIPLAB DASGUPTA: What is the source of your figure? (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The Government.

DR. BIPLAB DASGUPTA: You cannot take it lightly. You go through the Census Report. You must have the specific evidence for proving it. (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I am not in the Government. We get general information. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Without authenticating the statement that you are making, you should not speak in the House. (*Interruptions*)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर आप यही कहते हैं तो मैं . . (व्यवधान) और यह समझौता आपका आज का नहीं है जिस दिन से सरकार आई उस दिन से है । . . . (व्यवधान)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Why don't you say it is 20 crores? Why do you stop at two crores. (*Interruptions*) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : गृह मंत्री महोदय के मतलब की बात आ रही है । . . . (व्यवधान) देखिए यह केवल हथकंडे शोर मचा कर असलियत को छिपाने के हैं । मैं मानता हूं कि यदि केवल हजारों हैं तो भी क्यों हैं . . . (व्यवधान) . . . . और करोड़ों हैं तो भी क्यों हैं । . . . (व्यवधान) ठीक है क्यों हैं ? लेकिन आपका यह समझौता आज से नहीं है, आजादी के तुरंत बाद समझौता हुआ था। नेहरू-लियाकत अली पैक्ट था उसको भी आप ने तोड़ा, 1950 में इमीग्रेशन एक्ट बनाया आपने उसको लागू नहीं किया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों लागू नहीं किया ? इतना ही नहीं, पी०आई०पी० प्रिवेंशन आफ इनफिल्ट्रेशन फ्राम पाकिस्तान एक्ट 1964 में दूसरा बना है लेकिन कुछ नहीं हुआ । पहले 1950 में बना और फिर 1964 में दूसरा पेक्ट बनाया तो भी कुछ नहीं किया । क्यों ? चालिहा जी कुछ करना चाहते थे, वहां के मुख्य मंत्री थे उस समय के आपके यूनियन होम मिनिस्टर साहब श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने . . . . (व्यवधान) उन्होंने धमकी दी कि यदि तुमने कुछ किया तो आसाम की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। यही सारी परम्परा आज तक चली आ रही है ।

अभी किसिंगर महोदय यहां आए थे और मैं उन का उदाहरण देना चाहता हूं । एक विदेशी क्या कहता है और आप क्या समझते हैं ।

किसिंगर ने अपनी किताब में लिखा है :

Henry Kissinger, in his book "White House Years", has said and I quote: "Whether the turned nationalists or radical Bangladeshis would, over time, accentuate India's centrifugal tendencies. He is the man who wrote it years ago.

वह कुछ दिन पहले यहां आए हुए थे । 15-20 दिन पहले वह आए थे तो मुझे ध्यान आ गया कि इस पर कुछ भले आदमी ने कहा है । दूर का आदमी

लिखना है कि बंगलादेश शोषित रहे या कुछ भी रहे, वह आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को तरजीह देगा ।

That could see but you are blind.

आप आंख बंद करते है । कारण क्या है ? आप किस नशे में छिपे हुए हैं, जिस को हम लोग सुडो सैकुलरिज्म कहते हैं । आप कहां तक बढ़ गए । आई०एस०आई० की एक्टिविटीज सारे हिन्दुस्तान में फैली हुई हैं । आंख का अंधा भी जानता है कि यदि पाकिस्तान को गड़बड़ करना है और कर रहा है तो वह काश्मीर तक क्यों सीमित रहेगा । आप कह रहे हैं कि यह काश्मीर तक सीमित है, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां पर कि आई०एस०आई० का कोई - न कोई अड्डा न हो । आप उनकी तरफ आंखें मूंदकर बैठे हैं । इसका सबसे बड़ा उदाहरण "इसरो" है ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : माथुर साहब, आप जरा बैठें, मुझे कुछ कहना है । आपकी पार्टी के लिए 1 घंटा 30 मिनिट का कुल समय है आधा घंटा आप बोल चुके हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप और भी समय लेना चाहेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर देखा जाय तो मेरा अभी आधा भाषण भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा । मैं डिटेल्स छोड़ दूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप छोड़िए नहीं, लेकिन आपके दो और सदस्य बोलने वाले हैं और अगर आप अधिक समय लेना चाहेंगे तो उनका टाइम कट हो जाएगा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उनकी जिम्मेवारी मेरी है । मैं डिटेल्स छोड़ दूंगा ।

महोदया, "इसरो" में "रॉ" और आई बी० के बीच में डिफरेंसेस हैं । आइ०बी० आपको रिपोर्ट देता है, वह आपको पसंद नहीं आती । उसे सी०बी०आई० में बदलवाया जाता है । हाइकोर्ट का जज उस पर टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे देंगे । महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहा है कि हाइकोर्ट को ऐसे शब्द इस्तमाल नहीं करना चाहिए थे, लेकिन फैक्टर्स पर उनका ऑब्जेक्शन नहीं है । महोदया, इसमें एक और बात है, होम मिनिस्टर साहब चले गए, अच्छा होता, वह बैठे रहते । महोदया सी०बी० आइ० के एक एडीशनल डायरेक्टर जनरल एन०के० श्रर को आपने डिसमिस कर दिया । क्यों किया और किस बहाने से किया ? इस आदमी ने "इसरो" के सम्बंध में गहरी जांच कर के डॉक्युमेंट्स तैयार किए थी । पी०एम०ओ० के ऑफिस से फोन जाता है । उसकी फाइल मंगायी जाती है फाइल आती है तो उसमें कहा जाता है कि जब यह नौकरी में भर्ती हुए इन्होने उम्र का सर्टिफिकेट दिया, वह गलत था उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, लेकिन बाद में उसे ठीक करवा ली थी ।

On this ground he is dismissed. Who is responsible for this?

महोदया, "इसरो" के केस में एन०के० श्रर के बारे में अगर मैं गलत कह रहा हूं, अभी होम मिनिस्टर यहां मौजूद मैं और अच्छा होता वह बैठे होते, क्या आपने उन्हें सिर्फ इस बहाने से नहीं हटाया ? आपने हटाया ।

It is a fact. It is my information from a report of that Department.

तो आप यह कह रहे हैं और आपने सी०बी०आइ० डिपार्टमेंट का नाश कर दिया है । एक-एक इंस्टीटयूशन को आपने खत्म कर दिया है ।

महोदया, करप्शन का तो इसमें जिक्र ही नहीं है । करप्शन का तो मानें कांग्रेस वालों की आदत ही है । फिर इसका क्या जिक्र क्योंकि जिक्र तो उस बात का होना चाहिए जोकि अच्छी हो या नहीं हो । पुरानी बात का क्या जिक्र करना । वह मैं नहीं करना चाहता, फिर अर्जुन सिंह जी के पत्र की बात है और सिर्फ अर्जुन सिंह जी का पत्र जारी नहीं है . . (**व्यवधान**) . .

श्री हेन० हनुमनतप्पा : वह आपके लीडर बन गए हैं ? वह आपके दोस्त कब बने ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वह तो आपके लीडर हैं, हमारे लीडर नहीं हैं। यहां तो "घर का भेदी लंका ढहाए" वाली बात चल रही है।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: वह हमारी आपस की बात है। वह आपके लीडर कब बने ? आप उनके चेले कब बने ?... **(व्यवधान)**...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्योंकि उसका उस पर प्रभाव है। फिर वह क्या ग्रुप है....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) माथुर साहब, आप मुद्दे पर बोलिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: इंटर मिनिस्टिरियल ग्रुप की रिपोर्ट कैबिनेट को नहीं दिखायी गयी। लेकिन महोदया एक कहावत है न कि, "घर का भेदी लंका ढहाए।" मौलाना साहब नहीं बैठे हैं, कहते हैं कि "जनाजा घर वाले ही उठाते हैं।" अर्जुन सिंह जी ने इस सरकार का जनाजा उठाना शुरु कर दिया है। हम तो केवल फातेहा पढ़ देंगे। महोदया, किसी ने एक शायर से पूछा कि, मरने के बाद क्या होगा ? तो वह कहता है कि--

"बताएं हम तुम्हें मरने के बाद क्या होगा,

पुलाव खाएंगे एहबाब फातेहा होगा।"

उपसभाध्यक्ष जी, अर्जुन सिंह जी और उनके साथियों के जनाजा उठाने के बाद लोग पुलाव खाएंगे। तो लिहाजा मेरा कहना है कि जनाजा उठाने की तैयारी है, फातेहा पढ़ने की तैयारी कर लो भाई। ...**(व्यवधान)**... अब करप्शन का विषय आपने बता दिया, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं बहुत-सी चीजें छोड़ देता हूं।

SHRI V. NARAYANASAMY: Nobody can defeat the Congress (I) Party. You take that of your BJP. You take your Party first. First of all, stop the infighting between Mr. Murli Manohar Joshi and Mr. Advani.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: महोदया, मुझे क्षमा करें। आखिरी बात, आखिरी तो यह नहीं है, लेकिन आपके कहने पर सारा काट रहा हूं, वैसे शायद मैं दो घंटे बोलता।

महोदया, काश्मीर के सवाल पर आपने क्या किया ? सब परमात्मा जानता है। एक एक कदम पर आपने गलती की है और जानबूझकर गलती की है। हिन्दुस्तान आजाद होता है, फौजें लड़ रही हैं। अगर फौजें एक हफ्ता, पांच दिन और लड़तीं, तो सारा काश्मीर जीत जाते। दुनियां में कहीं आपने देखा है कि बढ़ती हुई फौजों के पैरों में जंजीर डाली जाय ? वह हमारा ही दुर्भाग्य पूर्ण दश है कि फौजें बढ़ती हैं, उनको चार-पांच दिन और मिलते, तो सारा काश्मीर जीतकर रख देते मगर उन बढ़ती हुई फौजों के पैरों में जंजीरें डाल दी जाती हैं, बेड़ियां डाल दी जाती हैं। यह राजनीति नीति है। आज आप यू.एस.ए. जाते है आपने एक गलती की तो आपको गिनाऊं भी, हर लम्हा आपने गलती की है। जिस इंसान पर आपने भरोसा किया था, वही आपको धोखा दे गया। आपको याद है, जिस दिन स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नहरु हमको छोड़कर: चले गये, उस दिन आपके मित्र शेख अब्दुल्ला बैठे थे, काश्मीर के उस हिस्से में पाकिस्तान का समझौता करने के लिए, जो आज की लाइन आफ कन्ट्रोल है। सारी कहानी बताऊंगा, तो दर लगेगी।

श्रीमती कमला सिन्हा : कम ही बताइए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: जी। आज के हालात में आपने चुनाव का वादा किया। जरूर चुनाव कराइए, हालांकि आज हालात नहीं हैं। क्या काश्मीर में कभी कोई चुनाव ईमानदारी से हुआ है? सन 1952 के चुनाव में शेख अब्दुल्ला ने क्या किया ? वहां कोई चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ। करप्ट लोगों से आपने समझौता किया। अगर काश्मीर की वैली के लोग यह शिकायत करते हैं,

कि केन्द्र में बैठी कांग्रेसी सरकार ने हमें धोखा दिया है, तो वह गलत नहीं कहते। यह उनकी गलती नहीं है। अब जिस आदमी को आपने गालियां दीं, कि यह बईमान है, फलां है, वगैरह वगैरह है, उसी के से आपने समझौता किया कर लिया। आपकी कोई नीति नहीं है।

महोदया, आज चरारे शरीफ में क्या हो रहा है? वहां जो लोग बैठे हैं, पनाह मांग रहे हैं। फौज बाहर खड़ी है, और टैररिस्ट अन्दर हैं। वह चलन्ज कर रहे हैं। यहां तक कहा जाता है कि आप जाइए, छुट्टी कर देंगे। यह क्या है? यह कोई लड़ने का तरीका है? यह क्या तरीका है? वहां की जनता, आम आदमी जो है, वह कह रहा है कि मैं भूख से मर रहा हूं मुझ दवा दीजिए। आप नहीं दे सकते। टैररिस्ट यह जानते हैं। पाकिस्तान के टैररिस्ट आपके महमान बने हुए हैं, आज भी चरारे शरीफ के अन्दर और हमारे यहां के जितने हिन्दू मुसलामन भाई हैं, वह आपके दुश्मन हैं, उनके लिए कुछ नहीं। यह आपकी पालिसी है। आप चुनाव जरूर कराइए, लेकिन चुनाव के बाद के नतीजे आपको मालूम हैं? शब्बीर जी आते हैं, आप बिल्कुल उनकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। आप जानते हैं कि वहां पैसा बाहर से आता है। आप कुछ करना नहीं चाहते, आप रोकना नहीं चाहते, केवल बहाना चाहते हैं। लगता है, आप ऐसी चीज पैदा कर देंगे, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय फौजें यहां आकर उपस्थित हो जायें।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं थोड़े में, क्योंकि समय की कमी है, कि बाहर के देशों का भी जिक्र किया गया। कहा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अमरीका गए थे। बड़ी तोप मारकर लाए। क्या तोप मारकर लाइए? बताइए, साहत? हम पाकिस्तान से समझौता चाहते हैं, अमरीका के पास जाते हैं। यह क्या है? यह एन.पी.टी. पर दस्तखत का जवाब नहीं हो रहा। किसने कहा कि जवाब नहीं हो रहा है। खुल्लमखुल्ला कोशिश की जा रही है, आपको दावत दी जाती है कि एन.पी.टी. पर दस्तखत कर दीजिये, हम आपको कौन्सिल में जगह दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप वहां नहीं गए? आपको बुलाया ही नहीं था? ...(व्यवधान)... मैं एक बात जानना चाहता हूं कि एन.पी.टी. पर आप दस्तखत नहीं कर रहे, गवर्नमेंट है आपकी। क्या आपको सरकार का जो सबसे फवरट है, सी.टी.बी.टी., कम्परीन्सिव टैस्ट बेनट्रीटी, आप उसका समझौता करने को तैयार हैं?

लेकिन क्या इंप्लीकेशन समझे हैं, आपने सी.टी.बी.टी. में। लोगे समझते हैं टैस्ट नहीं होगा, खत्म हो जायगा। जो आज यह छूट चाहते हैं हाईड्रो न्यूक्लिअर टैस्ट में। आपने देखा है वह सिमुलेशन कर सकते हैं, बनावटी एटमोसफयर सा बना सकते हैं। रशिया है अमरीका है, वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं और कहते हैं कि सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत कर दीजिये। मै आगाह करना चाहता हूं कि 'दोस्तो, कि सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने में पहले यह कम्प्रीहेन्सिव होने चाहिये। केवल हाइड्र न्यूक्लिअर टैस्ट के बारे में देखिए। ...(समय की घंटी)...खत्म कर रहा हूं

अन्तिम बात मैं फिडिफेंस के बारे में कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ से लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है। सब जानते हैं कि "अग्नि" और "पृथ्वी" के बारे में आज तक आपने फौज के हवाले नहीं की है। अमरिकन कहते हैं कि हमने नहीं कहा परमात्मा आपको सच्चा सिद्ध करे कि आप कुछ न कुछ तैयारी कर रहे हैं और दुनियां को नहीं बता रहे हैं। मेरी पार्टी का दावा है कि आप खुल्मखुला कहिए कि हिन्दुस्तान एक न्यूक्लिअर पावर होगा एटम बम बनायेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको रोक ले। प्रतिरक्षा के मामले में हम कभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, प्रतिरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। आप हिन्दुस्तान की अस्मत को बचना चाहते हैं, हमारी फौजों की हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे।

जब तक हममें से एक भी जिन्दा है, हम हिम्मत टूटने नहीं देंगे। फौज आप काश्मीर में भेजिए। "सण्डे टाइम्स" में खबर छपी है, आपने किसी के दबाव में फौज वालों को कहा है कि जो टैरेरिस्ट मारे गये हैं, जिनको कब्र में डाल दिया गया है, उन को निकालिए। कमाल है। फौज का यह कहना है कि जो टैरेरिस्ट मारे गये हैं, उनको निकालिए और निकालकर दिखाइए It is an insult to the army. It is an insult to the community. आप आर्मी का मिसयूज कर रहे हैं। आप आज रोज अलग बना देते हैं। आपने एक राष्ट्रीय राइफल बनाया, बिल्कुल ठीक है आपने कई हजार अफसर उसमें भेज दिए। आपने स्टैंडर्ड कम कर दिया। आपका खुल्लमखुल्ला ऐलान है कि जो स्टैंडर्ड पहले भर्ती के लिये थे, हम उनको नीचे ला रहे हैं। यह कैसा तमाशा कर रहे हैं, आप? इसके साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं कि आपने थ्रेट असेसमेंट कब किया? पिछली बार वह 1978 में हुआ और उसके बाद 1985 में हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने नया थ्रेट असेसमेंट कब किया है? 1978 और 1985 के बाद आज जमाना बदल गया है, दस साल बीत गये हैं, क्या आपके आरमामेंट जितने थे, वे पूरे हैं? यू हैव नॉट बिन इट। "अग्नि" या "पृथ्वी" की बात छोड़ देते हैं, आपने "अग्नि" और "पृथ्वी" के लिये कहा था कि प्रधान मंत्री के अमरीका से लौटने के बाद बात करेंगे, आपने क्यों नहीं की। अगर तैयारी नहीं है, तो आप जरूर तैयारी कीजिए, बात मत कीजिए और अगर तैयारी है, तो कोई कारण नहीं है कि आप "अग्नि" और "पृथ्वी" फौज के हवाले इस्तेमाल करने के लिए न दें।

अंतिम बात, दो मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): माथुर साहब, आप आलरेडी 45 मिनट बोल चुके हैं, आपके हिस्से में 45 मिनट आए हैं। आपके दो मैम्बर और बोलने वाले हैं, यह आक्रमण है, आपके साथियों पर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: यह मानना कि देशभक्ति की भावना पर हमारा राजनीतिज्ञों का ठेका है, यहां हर कोई देशभक्त है। देशभक्तों की कमी नहीं है। दोस्तों, आज तक किसी सरकार ने देशभक्ति के भाव को जगाया नहीं। मैं कहता हूं कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एक भावना है, जो सदियों तक एक साथ, एक संस्कृति के साथ पलकर पैदा होता है। आज से बहुत साल पहले एटम टूटता नहीं था, एटम तोड़ दिया। छोटा है, दिखता नहीं, लेकिन जब टूटता है, तो असीमित शक्ति पैदा होती है। उसी प्रकार देशभक्ति की भावना छोटा सा एटम है, इसे जगाइए, असीमित शक्ति पैदा होगी। यह देश मेरा है, संस्कृति मेरी है, इतिहास मेरा है, यह गौरव जागेगा, तो देश ऊंचा उठ जायेगा।

यह ठेकेदारी की जिम्मदारी मेरी है, आपकी नहीं है, सबकी है, इस देश की है। हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, इसाई है, किसान हैं, मजदूर हैं आपने भाव जगाया नहीं है। एक आप छोटे से भाव को जगा दीजिए। यह देश मेरा है, इसकी जिम्मदारी के लिये मरूंगा। थोड़ा सा भाव है। देश आपके लिए दुआ करेगा। बन्देमातरम्।

SHRI V. NARAYANAMY (Pondicherry): Madam Vice-Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks moved by my colleague, Shri Suresh Pachouri and seconded by Shrimati Jayanthi Natarajan to thank the hon. President for having addressed both the Houses of Parliament in the joint sitting on the 13th February, 1995. If one goes through the President's Address it gives a clear picture of the achievement of the present Government for the last four years and the policy and direction that this Government will follow in the coming year.

Madam, the Presidents Address can broadly be divided into five categories the development in the agricul-

tural sector, the development in the industrial sector, the social development in the country achieved by this Government, the Kashmir affairs and the foreign policy of the Government. I was carefully listening to the speech of my senior Member, Shri J. P. Mathur on the Motion of Thanks and I find that it has become a habit of the BJP leaders both in this House and outside to accuse the Congress Government as a pseudo-secular Government. I don't think they are aware of its meaning. It is quite unfortunate that a political party which has taken the line of Hindutva and which has been publicising to the world that India is a Hindu Rashtra accuses the Congress party which has sacrified its great leaders for nationalism and secularism of a pseudo-secular party. I am really pained to hear this from them because on national issues, all the parties have to come together. No one is superior to the other in nationalism. But, unfortunately, the BJP wants to accuse the Congress Government for narrow political ends. I fell really sorry for it. Even now, they have not changed their ways, even after joining the Government with the Shiv Sena.

I would like now to refer to the achievements of the previous Government. Every one who is sitting in this House are aware of this. The Janata Dal was supported on the one side up by the BJP and on the other side by the Left parties. What was the economic situation of this country in 1989? What was the foreign exchange position? What is the development in the agricultural sector? How many industries were closed down? What about the labour? They were suffering a lot. There was communal conflagration. Besides this, how many lives were lost in the Mandal agitation? Everybody knows about these things. Then, the National Front Government could not rule this country even for 11 months, in spite of the support given by the BJP and the Left parties. The next Government could not continue in office for more than six months. At that time, our foreign exchange reserves were about two thousand crores of rupees. The rate of inflation was more than 17 per cent. The people of this country could not get the essential commodities. Above all, the people had no security for their lives. Under those difficult circumstances, after the brutal assassination of our great leader, Shri Rajiv Gandhi, the present Government took over under the leadership of Shri P. V. Narasimha Rao. The new economic policy was formulated in June 1991. The economy started moving then. Today, in the agricultural sector, our production target is set at 187 million tonnes, which is unprecedented in the history of Indian agriculture. The credit goes to our farmers who are working hard. Despite the difficult climatic and other conditions prevailing in the country, our farmers are putting in all their efforts to see that the country is self-sufficient and that it is able to export agricultural commodities to other countries. Our foodgrain reserves today are more than 35 million tonnes.

SHRI JIBON ROY: But people are starving.

SHRI V. NARAYANASAMY: The people are starving in West Bengal because of your wrong policies. Don't talk to me about that.

Madam, we cannot find any queue in front of the ration shops today. The people go to the ration shops freely and get essential commodities. inflation, which was at a double-digit level, has been brought down to 8.7 percent. Earlier, it had gone up to 10 percent. Now, it has come down to 8.7 percent. But, unfortunately what to talk of understanding

the development that has taken place in the country they do not even admit it and they start criticising this Goverment, not on important issues that are haunting this nation, but on various extraneous issues. I do agree that there are problems for the farmers. Our Government is trying to solve those problems. The major problem is about fertiliser. I for one raised the issue of fertiliser subsidy to the farmers, because the subsidy that has been given by the Government is only on urea. In the case of other fertilisers, which are being used by the farmers, the prices have gone up because the subsidy has been removed. We are taking up this issue with our Government to see to it that the farmers get fertilisers at reasonable prices. We are not looking at the world with closed eyes.

Madam, if we go through the achievements in the industrial sector, we will see that because of the new economic policy, investments are coming in through the NRIs and through the multinationals. But we do not have a double-face like the other political parties have. If it is a case of West Bengal, the Prime Minister of Singapore can come, sign MOUs and start industries. The foreign investment is welcome there. But, when it comes to the Central Government signing MOUs, they say that this Government is mortgaging India to the multinationals. Now, it is ruled by a CPM Government which is opposing this policy here and adopting the same policy in their State. That is the point that I am making. If you want to challenge me you challenge me on that.

In the power sector alone, Rs. 35,000 crores' worth of investment has come. Our country has to compete with the developed countries today. India is a forerunner amongst the developing countries. The other countries are looking up to India in the matter of following these economic reforms. Today, India has to take a lead. But we do not have power. We do not have sufficient electricity. Without sufficient power, any number of industries that we may set up, it is not going to help us in any way. Therefore, Madam; the hon. President has clearly said that foreign investment is coming in all the sectors and the Government is making efforts to see that proper development takes place.

As far as the rate of industrial growth is concerned, it is 7.8 percent for the year 1994-95. Whether it is the coal industry or steel industry or in the area of infrastructural industries, it is on the high side. The foreign countries are looking towards India for their investments. Everyday, MOUs are being signed either by the Central Government or by the State Governments for bringing in more investments into this country. Madam, our small and medium industries are in a position to export. They send goods abroad for the purpose of earning foreign exchange. Today, the small scale industries alone are contributing more than 24 per cent of the total exports of our country and giving employment to millions of people. Millions of people are getting employment through the small scale industries which are doing about 24 percent of our total exports. Therefore, Madam; the opposition parties for the purpose of opposing this Government are trying to sidetrack this issue on petty matters and forgetting the achievements of this Government.

Madam, as far as the Economic Policy is concerned; our concentration is on the poor. We have been adopting pro-poor policies right from the day when the Government headed by our Prime Minister, Shri P. V. Narasimha Rao; took over. The problems of the Backward Classes have been solved by this Government. After the Supreme Court judgement on the Mandal Commission Report, the Government started implementing the 27 percent

reservation for the Backward Classes and it has been highlighted by the hon. President in his Address. More employment opportunities have been created for the Backward Classes as a result of the judgement of the Supreme Court. The Central Government is implementing the Supreme Court judgement and making the State Governments to follow suit. More emploment opportunities have been created for the Backward Classes.

Madam, this Government is concerned about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. For the purpose of giving financial assistance for self-employment and also for the purpose of giving benefit to the rural women who are living in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes families, allocation of funds for the Scheduled Castes Financial Corporation has been increased from Rs. 150 crores to Rs. 300 crores. The hon. President has also made a reference to this in his Address.

Madam, regarding provision of giving financial assistance, since the minorities felt that the 15-Point Programme that has been brought by the Government is not being fully implemented as one of its aspects was the formation of the Minorities Development Corporation, funds have been allocated and the Corporation was created by this Government. Therefore, the interests of the minortes and the people who are living below the poverty line have been taken care of.

Madam, as far as rural employment is concerned rural employment for the people who are living below the poverty line in the villages, especially in the agricultural sector and who go for employment opportunities under the JAWAHAR ROZGAR YOJNA and the IRDP—a total allocation of Rs. 30,000 crores has been made in the Eighth Five Year Plan. More than 80 per cent of these funds have been exhausted for giving employment opportunities to the rural poor. Fortunately or unfortunately, those schemes are being implemented by the State Governments. The employment opportunities are given by the State Governments out of the total funds provided by the Central Government. Therefore, Madam, the programmes that have fixed and for which the funds have been allocated by the Central Government through the Ministry of Rural Development, have been implemented in right earnest. But unfortunately, there is a hue and cry inside and outside the Parliament saying that this Gvernment is not for the poor and this Government is for the multinationals.

SHRI JIBON ROY: Is there any doubt?

SHRI V. NARAYANASAMY: Your Members are here to speak on this point. I am only speaking on the President's Address. Kindly bear with me. And they are telling that this Government is only for selling this country to multinationals. Madam, if anybody cumulatively reads the hon. President's Address to both the Houses of Parliament and also the Budget, it will be vey clear that 75 per cent of the total Budget allocations are meant for the rural poor, poor people living in the rural areas. Madam, the media, the propaganda that has been unleashed by the Opposition, ome forces within, are all trying to say that this Government is not for the poor. The food subsidy that has been given by the Government exceeded the target of Rs. 5500 crores. The fertilizer subsidy is Rs. 5000 crores. The fact is that the funds have not been reduced but the publicity is not there.

Some of the State Governments even for giving some small benefits to people, arrange big functions in public and get publicity. But, unfortunately, there is a campaign of the Opposition for vilification against

the ruling party. Even though our achievements are there, they have not been highlighted. Therefore, I would like to submit that we have to accept the shortcomings...

SHRI CHATURANAN MISHRA: Shortcomings would be in the President's Address!

SHRI V. NARAYANASAMY: We have to accept the hard realities. The Opposition leaders sitting here should accept these. Of course, there is one area where there is primary... (*Time-bells rings*)... Madam, I have not yet started.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Your Party has one hour and ten minutes. I have the names of so many Members before me. You tell me how to go about it. Shall I cut the time of others and give you more time?

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I have got a lot of points to make, but I will be brief.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, he was saying about publicity. How he is...

SHRI V. NARAYANASAMY: Not about advertisement. I am telling about your advertisements.

Madam, as far as the Government's achievements are concerned, as I have submitted here, they are many.

Fund allocation has been made by the Government in regard housing problems faced by the urban poor. Funds have also been allocated to the rural sector. People migrate from rural areas to the urban cities for the purpose of getting employment. There they are unable to get houses of their own. The Government is concerned about it and an ambitious programme of constructing a million houses has been initiated.

Madam, on the economic, agricultural and industrial fronts; the Government's achievements are laudable.

Everybody knows the issue of Ayodhya. It is a very important issue. It has been considered more important especially by the people belonging to the minority community. This Goverment has to solve it. The Hon. President has made a reference to it also. On the reference made to it, the Supreme Court has made two observations. Firstly, the acquisition of land has been upheld. Secondly, it has ruled that the dispute relating to the title of the property has to be adjudicated in the courts. The matter is pending. As far as this is concerned, the Government will take a decision to solve this problem. It is a major problem that has been haunting the minds of the minority community. Unfortunately the people who have been the real culprits in the demolition of the Babri Masjid went scot-free and we are being blamed for this! Everybody knows it also. It is a concern of everybody. We want peace in this country. We want the people of all communities to live together. India is secular, and our credentials have been there for a long time. Even the foreign countries appreciate India's stand on secularism. Therefore, Ayodhya is of prime importance to this Government. As far as Jammu & Kashmir is concerned, there is an annoucement by the Governor that elections are going to be held soon. The situation was not favourable earlier. The militants' activties were on the higher side and the people of Jammu & Kashmir, especially of the Kashmir region, were feeling insecure. Thousands of militants were killed. Our *jawans* were killed. Innocent people were killed. There was no peace in that area. Gradually, normalcy is returning in that region. For the last two or four months we

4.00 P.M. find that the situation in Jammu and Kashmir

is peaceful, by and large. How long a Government can keep a particular State under President's Rule? A popular Government is to be installed, that Government has to take over and it has to administer the State for the purpose of development. In Jammu and Kashmir, which was a peaceful State and which is primarily an area of tourist importance, because of terrorism these developmental activities have come to a standstill. Therefore, the people of Jammu and Kashmir find that in Punjab, which was also a terrorism-prone area, now peace has returned and popular Government has taken over and developmental activities are going on. The people of Jammu and Kashmir also want peace in that area and want people from various religions to live there and to live in harmony. I am very grateful to the people of Jammu and Kashmir that they want peace in the area and, fortunately, for the last six months they have rejected terrorists in Jammu and Kashmir. The people who had given protection in the earlier period have now rejected terrorism and they have said that militancy should be no more be there in Jammu and Kashmir and Jammu and Kashmir should a part and parcel of the country. Madam, terrorism in Jammu and Kashmir is the total make-up of Pakistan. Pakistan in the international forum and also in the Islamic forum has been raising the issue of Jammu and Kashmir and it has been making false claims, ignoring the Simla Agreement. And as far as we are concerned and as far as our Government is concerned we are prepared to talk to anybody within the framework of the Constitution. Even if the people are militants, if they are prepared to give up arms and if they accept the Constitution, we will talk to them and we will try to resolve the issue of Jammu and Kashmir. Therefore, Madam, I am very happy that there is going to be a solution for Jammu and Kashmir and the Government will hold elections in Jammu and Kashmir soon. Madam, as far as the foreign Policy of this Government is concerned, the hon. President took pains to see that three pages of his speech were in reference to the foreign policy of the Government. In the history of our Indian Government, foreign dignitaries' visit to this country for the last two or three years are exceedingly more. The last visit one by the Iranian President, was also successful. Our hon. President, the Vice-President of India and also the Prime Minister have visited several countries and they have highlighted the Indian Government's foreign Policy and the econonic policy of this Government. It has been welcomed by all the countries. And all the countries including the United States are trying to keep good retaliions with India. Especially, Madam, one point I would like to ask on the Pressler Amendment which is relating to giving military aid to Pakistan. There was a lobby in the United States for the purpose of removing the Pressler Amendment for the purpose of giving military aid at the time when the Pakistan Prime Minister, Mrs. Benazir Bhutto visited the United States. But the Congressmen there and the people of the United States wholeheartedly have said that Pakistan is a terrorist States and, therefore, giving militay aid to Pakistan is going to create problems not only for India but also for the adjoining countries, and therefore, the Pressler Amendment has to continue. Madam, this is one of the biggest achievements of this Government.

Apart from that, making Pakistan withdraw its resolution in the U.N. relating to Jammu and Kashmir is also the biggest achievement of this Government. When the hon. President highlighted the acievements of our Government, our senior Member, hon. Shri Mathur was trying to criticise the Government in name of infiltration and Bangladeshis. He was

speaking the voice of the Shiv Sena and not of the BJP. It is quite unfortunate.

Madam, I will raise only two or three more points.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): But try to be brief.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am going to be very brief I would like to highlight only one or two points.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Leave some points for your colleagues also.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, there is one more issue which is of a primary concern and I would like to raise it in this House. This issue relates to the proceedings of the Jain Commission which are pending and I would like the Prime Minister to reply to that part also. In this House we have been consistenly raising this issue of the proceedings of the Jain Commission and the matter which in pending before the Designated Court in Madras on the assassination of our leader Shri Rajiv Gandhi. Madam, we have been reading Press reports that some of the documents have not been filed by som of the agencies before the Jain Commission. I know pretty well that the Home Minister and the Prime Minister have been monitoring the progress of the matters before the Jain Commission and before the Designated Court. But, unfortunately, some of the agencies have not filed the documents. This is the observation of the Jain Commission. I would like the hon. Prime Minister, when he addresses this House to enlighten me on that because the misgivings in the minds of the people about the Jain Commission have to be removed.

Madam, another aspect which is also of a primary concern to everybody, is the matter of price situation that is prevailing in the country. Now, the price situation in spite of the fact that there is economic growth, remains a matter of concern. In his Address the hon. President has mentioned that the price situation has to be controlled. It is a matter of concern, as far as the price situation is concerned. Madam, inflation has come down; in spite of that for some items prices have been increasing and we are not able to control them. I would like to submit that though the essential commodiiies are available, the Government has to supply those items when those are available with them so that the price situation can be controlled. The middle classes, the upper-middle classes and the richer classes can afford, but it is the poor people living on their meagre wages, who feel the pinch of it. Therefore, the hon. President has rightly made the observation that the price situation has to be controlled by the Government for the purpose of seeing that there is no price increase in the various important essential items which people want for their livelihood.

Madam, there are many speakers and since you are asking me to conclude, I will conclude. There are so many other subjects on which I want to speak. ..(*Interruptions*).. I will speak on them when the Budget is taken up. Madam, I will make a final point.

AN HON. MEMBER: Why final?

SHRI V. NARAYANASAMY: Because she says that time is not there.

THE VICE-CHAIRMAN MISS SAROJ KHAPARDE): I am not saying. Your Party has one hour and ten minutes. There are 13 names in the list before me. Moreover I have given you sufficient time.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want to make a point about the situation prevailing in the North East. With that, I will conclude.

We have a Congress Government is most of the North Eastern States. In some of the States, particularly, in Tripura and Manipur in the border areas, there has been an escalation in the militant activities. These militants are infiltrating into Assam also. I have reports that terrorism in Assam and the other North-Eastern States has started brewing in spite of the fact that we have normalcy in other parts of the country. Therefore, I want the Government to pay attention. Even after the elections in Manipur, the problem is there. The situation in Tripura is also not peaceful. In Assam also, terrorism is trying to raise its ugly head. Therefore, I want to the Government to pay attention to the controlling of terrorism in the border areas.

With these observations, I support the Motion moved by Shri Suresh Pachouri. I thank you, Madam, for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (KUMARI SAROJ KHAPARDE): Shrimati Kamla Sinha. Kamla Sinhaji your party has fifty six minutes.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): I know, Madam. I am well aware of the fact.

महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण हुआ था, उसके ऊपर अभी हमारे सदन में धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है और यह वाद-विवाद उसी के साथ है । मैं इस पुस्तक को, उनके अभिभाषण को बहुत गौर से पढ़ रही थी । पढ़ते-पढ़ते मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे राष्ट्रपति जी को उनकी सरकार सही मायने में सलाह नहीं देती है और बहुत बात अंधेरे में रख करके उनसे कहलवाया जाता है और नहीं कहलवाया जाता है । इस अभिभाषण में जो स्थिति है, उसके बारे में सही स्थिति का कोई उल्लेख ही नहीं है । जैसे राष्ट्रपति जी ने कुछ प्रान्तों के चुनाव के बारे में, जैसे प्वाइंट नं० 3 में उन्होंने कहा है कि :

"Polls in Goa, Sikkim Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have been peaceful."

लेकिन उन्होंने मणिपुर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और सिक्किम में एक प्रोपग्रप सरकार 30-32 की असेंबली में 10 की सरकार और 10 की पार्टी की सरकार बताया उनकी सरकार ने और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है । बिहार के चुनाव के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा । यह बहुत ही दुख की बात है । ... (व्यवधान) बाद में हुआ। ... व्यवधान लेकिन इतना तो कह सकते थे कि बिहार में चुनाव हम समय पर करवायेंगे । यह बात तो कह सकते थे । इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है ।.... (व्यवधान) महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूं और इस सदन में मैं अपनी बात रखना चाहती हूं । पहले तो चूंकि हमने कहा कि राष्ट्रपति जी ने बिहार के चुनाव के संबंध में अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया, मैं उसी से अपनी बात शुरू करना चाहती हूं ।

महोदया, यह सब को मालूम था कि बिहार की असेंबली का चुनाव 15 मार्च के पहले हो जाना चाहिये था और नई असेंबली का गठन हो जाना चाहिए थी । लेकिन साजिश पहले से चल रही थी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और उस साजिश के तहत दिन का हेरा-फेरी होता रहा । एक दफा तय हो उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाए और उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाए । इस काम में इलैक्शन कमीशन ने काफी बड़ी अहम भूमिका निभायी, किस ढंग से सारी बात हो गई, यह सब आप लोग जानते हैं और उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है । नतीजा यह हुआ कि बहुत थोड़े समय के लिये राष्ट्रपति शासन लागू भी किया गया, लेकिन बिहार की जनता ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि चाहे जितना हमें सताओं, हम अपनी राय जाहिर करके रहेंगे और बिहार में इस बार जो वोट दिया... वह वोट गरीब जनता का वोट है, वह वोट सताए हुए लोगों का वोट है और उस वोट ने यह

साबित कर दिया कि सो-काल्ड जो ऊंचे लोग थे, लाठी चलाने वाले लोग थे और जो बूथ्स के लुटेरे थे, वह इस बार नाकामयाब रहे क्योंकि लोगों ने ठान ली थी. .

डा० जगन्नाथ सिंह (बिहार) : महोदया, पूरी लूट से इन्होंने वहां वोट जीते और अब यही बात वह खुद कह रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह इस सदन को भ्रम में न रखें, जनता को गुमराह न करें और जिम्मेदारी के साथ बोलें। सारे दस्तावेज मौजूद हैं, अब संविधान में यह अनुमति नहीं है कि चुनाव याचिका के बगैर कोई सुनवाई हो, लेकिन वहां पूरी सरकार बेईमानी और लूट से बनी है, इसलिये वे चुनाव की चर्चा न करें तो अच्छा है।

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदया, डा० जगन्नाथ मिश्र जी की कृपा से कांग्रेस पार्टी बिहार में 72 से 27 पर आ गई है।

डा० जगन्नाथ मिश्र : जहां चुनाव हुआ ही नहीं, पूरी धांधली और बेईमानी हुई हो तो, फिर क्या होना?

श्रीमती कमला सिन्हा : छोड़िए, बिहार की जनता ने आपको भी पहचान लिया है. . . . (**व्यवधान**) . . . देखिए, दोनों में कैसी दोस्ती है?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, जब डकैती पड़ती है, तो सारा गांव इक्कठा हो जाता है . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : माथुर साहब, जब आप बोल रहे थे तब आपके भाषण के समय किसी महिला ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, और अब जब एक महिला खड़ी है, बोलने के लिए तो उन्हें आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर महोदया, मैं चेयर पर बैठे हुए को महिला या पुरुष नहीं समझता, खाली चेयरमैन समझता हूं। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे कुछ नहीं कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : एक-दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं होनी चाहिये और उनको बोलने का मौका देना चाहिये, आप फिर उठ गए. . (**व्यवधान**) . .

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदया, तमाशा तो यह हुआ कि बिहार में जनता दल की सरकार वापिस न आए, इसके लिये कांग्रेसी सरकार ने इलैक्शन के जरिये और सेन्ट्रल फोर्स के जरिए जितना संभव हुआ, नंगा नाच बिहार में किया। वहां की सारी रिपोर्टिंग आती रहीं, लेकिन मीडिया ने हम लोगों को वहां राइट आफ कर दिया था, यह भी हम जानते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने सच्चाई प्रमाणित कर दी, जोकि पूरे देश और दुनियां के सामने है। महोदया, 28 मार्च तक चुनाव होते रहे, गुजरात और महाराष्ट्र से इलैक्शन के रिजल्ट्स आ गये फिर भी नतीजा यह है कि बिहार में जगन्नाथ मिश्र जी पैर के नीचे से धरती खिसक गई।

श्री संघ प्रिय गौतम : किधर गयी?

श्रीमती कमला सिन्हा : किधर गयी, यह हमें नहीं मालूम, लेकिन खिसक तो गयी और वह धम से गिर गये।

डा० जगन्नाथ मिश्र : महोदया, खिसकी नहीं जबरन छीन ली गयी।

श्रीमती कमला सिन्हा : अरे, कुछ तो शर्म कीजिये।

डा० जगन्नाथ मिश्र : चुनाव आयोग की मंशा को भी आपने खत्म कर दिया। इन्होंने अर्ध-सैनिक बल को प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया, चुनाव आयोग का उल्लंघन किया, यह दस्तावेजी सबूत हैं। चुनाव आयोग ने जितनी बातें कहीं, इनकी सरकार ने उन्हें नहीं सुना, जिला पदाधिकारियों ने उनका पालन नहीं किया, यह तो पूरी धांधली से हुआ चुनाव है, बेईमानी का चुनाव है।

श्री चतुरानन मिश्र : ऐसा हो सकता है कि आप जहां-जहां से जीते हैं, वहां फिर से चुनाव हो जायें।

डा० जगन्नाथ मिश्र : लालू को हटा दीजिये । लालू को हटाकर चुनाव कराइए, असलियत सामने आ जायेगी । यह तो जोर-जबर्दस्ती और बेईमानी का चुनाव है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : पहली बार तो आपकी बेईमानी बन्द करायी है।

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل : پہلی بار تو آپ کی بے ایمانی بند کرائی ہے۔

श्री चतुरानन मिश्र : जहां हत्यायें होती रही . . . (**व्यवधान**) . .

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मिश्र जी, हम लोग सदन में राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, या बिहार पर ?

श्री चतुरानन मिश्र : यह तो आपको उनसे पूछना चाहिए । हम तो आपकी मदद के लिए आये, आप हम से ही पूछ रहीं हैं ?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप तो इतने सीनियर मेंबर हैं और जगन्नाथ मिश्र जी भी सीनियर मेंबर हैं । बिहार का दंगल आपने यहां सदन में क्यों शुरु कर दिया ?

श्री चतुरानन मिश्र : हम तो आपको मदद के लिये आये हैं । आप उनको कहिये न ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं जगन्नाथ मिश्र जी और चतुरानन जी दोनों को कह रही हूं । . . (**व्यवधान**) . .

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : अब आपका फैसला मान लिया है, अहलूवालिया जी, इसलिए खामोश बैठिए।

†[ ]Transliteration in Arabic script.

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل : اب آپ کا فیصلہ مان لیا ہے۔ آہلووالیہ جی اس لئے خاموش بیٹھیے۔

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैं इन दोनों मिश्रा के बीच में नहीं आता । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती कमला सिन्हा : एक मिश्रा तो बड़े सनामधनी हैं, बहुत करामात दिखाया था, इन्होंने बिहार में और दूसर बेचारे यहां दिल्ली में थे । मुझे कुछ लेना देना नहीं है, दोनों मिश्रा की लड़ाई में । यह मिश्रा मिश्रा लड़ते रहे और बिहार की जनता ने बात साफ कर दी कि अब मिश्रा-मिश्रा से काम आगे चलने वाला नहीं है । एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बार के चुनाव में यह प्रमाणित कर दिया कि बिहार में जो बड़े ठेकेदार लोग थे वोट के, उन्होंने जो बड़े-बड़े क्रिमिनल को खड़ा किया था, उनको जनता ने वोट नहीं दिया और इस बार बिहार की असेम्बली में वह लोग, जिनका क्रिमिनल रिकार्ड है, जीतकर नहीं आये । खैर, जाने दीजिये । आपने कहा कि बिहार की बात क्यों हो रही है ? चूंकि मैं बिहार की हूं, इसलिए बिहार की बात कहना जरूरी था।

महोदया, इस संदर्भ में मैं एक दो बातें कहना चाहती हूं, जो बिहार की होंगी । उन पर आप टोकिए मत । बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और यह बिहार का पिछड़ापन आज से नहीं, आजादी के बाद से ही शुरू हुआ है, जिसमें जगन्नाथ मिश्र जी, का खुद का और उनकी पार्टी की केन्द्र सरकार का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है।

श्री ईश दत्त यादव: पिछड़ा करने में ?

श्रीमती कमला सिन्हा : जी, पिछड़ा

†[ ]Transliteration in Arabic script.

करने में। इनका बिहार को पीछे धकेलने में बड़ा भारी योगदान है, उसका मैं केवल एक उदाहरण देती हूं कि बिहार में जितना देश का कोयला उत्पादन होता है उसका 40 प्रतिशत बिहार में होता है। अब 40 कह दीजिए या 45 कह दीजिए, फर्क नहीं है, मगर होता है। बिहार में जो बिजली की जरूरत है, वह 3000 मैगावाट की काम चलाने के लिए है, हमारी इन्सटाल कैपसिटी 1400 मैगावाट है, उत्पादन होता है तीन, साढ़े तीन सौ पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार के पास बार बार हम लोगों ने कहा कि हमारे यहां कुछ बिजली का प्रबंध करा दीजिए। एक हाइडल प्रोजक्ट कोयल कारो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसके लिए कहा। बिहार सरकार ने फरवरी, 1995 में जो पत्र लिखा था विद्युत मंत्री साल्वे साहब को, उससे पहले साल्वे साहब ने एक फैसला यह कर लिया कि बिहार को कोई पैसा नहीं देंगे, कोई मदद नहीं देंगे और उसके बाद जो पत्र लिखा, उसमें यह लिखा हुआ है—

"I am again bringing to your notice the state of affairs regarding proposed Koel Karo Project (710 MW). This hydel project is very vital for improving thermal-hydel mix in Bihar in particular and North-Eastern Zone in general. But unfortunately the Ministry of Power is not attaching proper importance to this Project and rather it has been intimated that NHPC is not in a position to execute the Project etc., etc....."

महोदया, यानी बिल्कुल सौतला व्यवहार करके, बिहार पिछड़ा ही रहे, इसमें उन्होंने मदद की और कोयल कारो प्रोजक्ट को चालु नहीं होने दिया। यह तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया।

महोदया, अब विदेशों से बड़ा पैसा आ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आफ इकोनमी हो गया। राष्ट्रपति महोदय, ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है कि ग्लोबलाइजेशन आफ इकोनमी से हमारे यहां बाहर से मदद हो रही है, 52 मिलियन अमरीकन डालर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है पावर सेक्टर में। महोदया, एक कहावत है:

Carrying coal to New Castle.

जिसका पेट भरा हुआ है, उसी को भोजन देना। तो जितने प्रान्तों में बिजली की कोई कमी नहीं है, उन्हीं प्रान्तों में बिजली लगाई जा रही है, उसी पैसे से, लेकिन जहां बिजली की आवश्यकता है, पूर्वी प्रान्तों में, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के प्रदेशों में, उड़ीसा, बंगाल में, जहां बिजली के लिए पैसा नहीं लग रहा है, लग रहा है, दक्षिण प्रान्तों में, जहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

महोदया, ग्लोबलाइजेशन आफ इकोनमी की बात पर मैंने चर्चा की। ग्लोबलाइजेशन आफ इकोनमी के तहत हमने अपना दरवाजा खोल दिया, विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा भी है कि विदेशी इन्वैस्टमेंट हमारे यहां आ रहा है।

अब कितना विदेशी इन्वेस्टमेंट आया, इसके आंकड़े अगर मैं आपको दूं तो समय काफी जाया होगा, मैं केवल विदेशी इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या रहा है उसके बारे में एक उदाहरण देना चाहती हूं। एक विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आया—पेप्सी कोला का। अब पेप्सी कोला यहां क्या कर रहा है? अपने यहां से हमें शर्बत तो जरूर लाकर पिलाएगा लेकिन साथ ही साथ पूरे अमेरिका का प्लास्टिक का डम्प यहां बन रहा है।

The Pepsi's involvement in both producing and disposing of plastic waste in India: Under Pepsi's two-part scheme, plastic of single use disposable bottles are manufactured in India and exported to the United States and in Europe, while toxic bi product of the plastic production processes stay in India.

टैकिसक प्रोडक्ट वह वापिस नहीं भेजते हैं, वह हिन्दुस्तान में ही इस्तेमाल होगा।

Used plastic bottles are then returned from these countries to India.

और पूरी दुनिया में जो पेप्सी का खाली बोतल होगा, वह हिन्दुस्तान में डम्प हो रहा है।

What is this nonsense?

इससे किस को क्या नौकरी मिल रही है कितना इम्प्लायमेंट जेनेरेशन हो रहा है?, राष्ट्रपति जी ने कहा कि इम्प्लयमेंट जेनेरेशन होगा । यह कब होगा, मैं जानना चाहती हूं ? हिन्दुस्तान में पेप्सी किसके साथ मिलकर बोतल बनाती है, एक कम्पनी है--फ्यूचरा-फ्यूचरा और पेप्सी दोनों मिलकर इम्पोर्ट करने हैं और यहां डम्प कर रहे हैं। तो पेप्सी का उदाहरण है जो प्लास्टिक वेस्ट का डम्पिंग ग्राउंड हिन्दुस्तान को बना रहे हैं ।

This is not leading India in to the path of economic prosperity. Thts is leading India into a dumping ground of international world under the globalisation process.

महोदया, हमारे देश में सरकारी उपक्रम चल रहे थे एक अर्थनीति के तहत, कुछ खुला कुछ सरकारी इस तरह की इस देश की अर्थनीति चल रही थी लेकिन यह सरकार जो नई अर्थनीति चला रही है, उसके तहत इन्होंने पब्लिक अंडरटेकिंग्स को खत्म कर देना है और जो बड़े-बड़े मुनाफा कमाने वाले पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके शेयर को बाजार में बेच देना है जो रोजी-रोजगार में लगे हुए हैं श्रमिक हैं उनकी संख्या को घटाना है और यह काम पिछले चार साल से चल रहा है। इस काम के तहत 1100 करोड़ रुपए सरकार ने बी. आर. एस. के मद पर 70,000 लोगों को नौकरी में बाहर निकालने के लिए खर्च किए हैं लेकिन नौकरी में लगाने के काम के लिए उतना रूपया नहीं लगाया गया है ।

महोदया सरकार जो करती है दूसरे प्राइवेट फैक्टरी वाले भी वही करते है। बड़ा भाई जिस रास्ते पर जाता है, छोटे भाई भी उसी रास्ते पर चलते हैं । नतीजा क्या है कि इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हाऊस--टाटा कम्पनी, टाटा कम्पनी में 70,000 लोग काम करते हैं टाटा कम्पनी ने एक प्रोग्राम बनाया है तीन साल में 15000 श्रमिकों को नौकरी से निकालने का काम चालू है । जो और छोटे-छोटे उद्योग हैं उन्होंने भी इसी तरह से छंटाई का काम चालू कर दिया है। केवल टैक्सटाइल सैक्टर में 1,20,000 लोगों की छंटाई हो गई लेकिन श्रमिकों के कल्याण के लिए जो काम होने चाहिएं, वे नहीं हुए । हम अगर कोयला उद्योग को ही ले लें तो कोयला उद्योग में वेतन समझौता 1 साल होने वाले हैं, अभी तक नहीं हुआ, समय बढ़ता ही जा रहा है लेकिन साथ-साथ यूनिलेटरली मालिकों में जो पिछला समझौता था, मैं केवल दो मुद्दे ही बताना चाहती हूं, उसमें एक क्लाज था 9-4-3 यानी जो श्रमिक बीमार हो जाता था काम के लायक नहीं रहता था वह रिटायरमेंट के दो-तीन साल पहले एक दरख्वास्त देकर यह कहता था कि अब चूंकि मैं किसी काम के लायक नहीं रह गया इसलिए अब मेरी जगह मेरा लड़का या लड़की काम करेगी, अब वह बंद हो गया। यूनिलेटरली उस पर मॉरोटोरियम लग गया। जो काम करते हुए मर जाए, उसकी जगह नौकरी में लेने का प्रावधान है, उसमें भी रूकावट आ गई। नौकरी नहीं मिल रही ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि बाल श्रमिक हमारे देश में हैं । उनके कल्याण के लिए एक बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया है । बड़ी खुशी की बात है कि आयोग का गठन किया गया है। लेकिन वह आयोग क्या क्या काम करेगा और कितने बाल श्रमिकों को प्रति वर्ष उनकी पढाई-लिखाई की व्यवस्था करके उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करेगा इसकी कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं है । हमारे देश में चार करोड़ से अधिक बाल श्रमिक हैं ।

महोदया, औरतों के बारे में अगर बात न करें तो यह बहुत अन्याय होगा । क्योंकि इस देश की आधी आबादी औरतों की है । जन्म से पहले ही हमारे ऊपर अन्याय हो जाता है । जो महिलायें नौकरी करने भी जाती हैं, एक तो नौकरी के समय उसको कोई प्रिफेंस नहीं, कोई सुविधा नहीं और काम की जगह पर उसके ऊपर अत्याचार भी होता है । इसके साथ-साथ दिनों-दिन औरतों के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार बढता जा रहा है, मैं उसके संबंध में आपके सामने थोड़े से आंकड़े रखना चाहती हूं । स्टेटिस्टिक्स यह कहती है कि :

Statistics reveal that a woman is

raped every 55 minutes and a dowry death is reported every 102 minutes in the country.

एक ऐसे देश में हम हैं। हम इसको जगल का राज भी नहीं कह सकते हैं, हम इसको हैवान का राज कह सकते हैं। जहां आदमी नहीं इंसान नहीं, हैवान बसती हैं यहां पर।

Every 26 minutes a woman is molested; and every 7 minutes one act of criminal offence against a woman is committed. Dowry death cases in the country were up from 127 in 1993 to 146 in 1994. Martial cruelty cases

109 से 982 हो गया है। इसी तरह से दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

Up to 1992, there were 55 cases. There are 127 persons under trial for rape cases of which 86 per cent cases are still pending.

कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। औरतों के प्रति तो कोई न्याय होता ही नहीं है। जहां इस तरह के केसेज में 86 प्रतिशत केसेज अभी भी लम्बित हों, उनमें सजा न हुई हो, तो फिर हम न्याय के लिए कहां जाएं?

संविधान में औरतों को सब अधिकार दिए हैं, बराबरी का अधिकार है। लेकिन संविधान का अधिकार अपनी जगह पर है और उसका उपयोग दूसरी जगह पर। कोई उपयोग हो नहीं पाता। इसी सदन में बारम्बार बातें हुई हैं मीडिया के बारे में, दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन में भी हम लोगों ने खुला बाजार कर दिया है। तरह-तरह का विदेशी एडवर्टाइज़मेंट तरह-तरह का सिनेमा, तरह-तरह का प्रदर्शन और इसके फलस्वरूप इस देश में क्राईम बढ़ता ही जा रहा है, खासकर के टीनेज क्राईम इतना बढ़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति जो कुछ हमारे पास था, उस सबको आप बरबाद कर देंगे तो फिर किस धरती पर हम खड़े होंगे?, किस बुनियाद पर हम खड़े होंगे? कहां जाएंगे हम? हमारे पास अपना तो कुछ कहने के लिए होगा नहीं? कहा जाता था कि औरतें देवी हैं। हर नारी को मां समान देखो। लेकिन यहां तो हर नारी उपभोग्या है। यह सिखाया जाता था कि कोई चीज छुओ नहीं, अगर गिरा हुआ है तो। उसे पत्थर समान मानो। लेकिन आज तो दूसरे का सामान छीनकर अपना ही पेट भरना ही बड़ी बात हो रही है। हमारी सभ्यता ही यही हो रही है। इसी सभ्यता के तहत जीना है इस देश को। राष्ट्रपति जी ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उनको कहना चाहिए था कि भारत रसातल में जा रहा है और हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यह बात उनको कहनी चाहिए थी। मैं बड़े अदब के साथ इस बात को कहना चाहती हूं।

महोदया, यह जो बहुत बड़ी भूल हुई है जिस बात का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने नहीं करवाया, वह यह कि हमारे देश में पॉपुलेशन ऐक्सप्लोज़न जो है, जो आबादी बढ़ती जा रही है निरंतर, उसके ऊपर कैसे अकुंश लगाएंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ इकनॉमी के बारे में है, प्राइस कंट्रोल के बारे में है' इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में है लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन जो दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसके बारे में जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को ठीक ढंग से नहीं अपनाएंगे, इस देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं काम करेंगे तो फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये चट्टान में सब कुछ चूर-चूर हो जाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में रहने के लिए जमीन नहीं होगी, घर नहीं होगा, अनाज पैदा करने के लिए जमीन नहीं होगी और जितने जंगल पहाड़ हैं, वे सारे कट जाएंगे जंगल, पहाड़ बरबाद हो जाएंगे लेकिन ये धरती, ये भारतवर्ष, ये हमारा अपना देश है, यह नहीं रहेगा, बरबाद हो जाएगा। इसको अगर बचाना है तब फिर अपने देश में आबादी को किस ढंग से कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत गंभीरता-पूर्वक सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा सरकार को।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगी। अभी-अभी पिछले साल अप्रैल महीने में हम लोगों ने एक दुनियावी समझौता किया है गैट रिजॉल्यूशन और अब तो नहीं रहा, अब तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है।

एक माननीय सदस्य : गैट खत्म हो गया है।

श्रीमति कमला सिन्हा : मालूम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजशन हो गया है, यह भी मालूम है। अब हमको पेटेन्ट ऐक्ट को पास कराना, है तो सरकार उसको लाना चाहती है तरह-तरह की बातें कर रही है। इस पेटेन्ट एक्ट को तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया है लेकिन हमको वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड और डब्ल्यू०टी०ओ० के निर्देश पर पेटेन्ट ऐक्ट को पारित करना है ताकि हिंदुस्तान की बौद्धिक सम्पदा कुंठित हो जाए। यह इसी के लि किया जा रहा है।

महोदया, दुनियां में तरह-तरह के सम्मेलन होते हैं। अभी हाल में एक सम्मेलन हुआ मार्च महीने में। चुनाव छोड़ कर हमारे प्रधान मंत्री जी अपना एक डेलिगेशन लेकर वहां गए थे–कोपेनहेगेन सोशन सम्मिट में, ये सोशल सम्मिट क्यों हुआ? इसलिए जहां कि दुनियां के सारे देशों के लोग इकटठा हुए और उन्होंने चिंता जाहिर की कि धनी देश तो धनी है वह अपने गरीब लोगों के लिए क्या करे? जैसे अपने यहां महल में रहने वाले दो टुकड़े रोटी के फेंक देते हैं गरीबों के लिए तो उसी तरह कुछ करने के लिए ये भी सोच रहे थे। सच तो यह है कि दुनियां की दो-तिहाई सम्पत्ति के मालिक दुनियां की वन-फोर्थ पॉपुलेशन है और उसका वे उपभोग करते हैं। बाकी सारे लोगों को उसका उपभोग करने के लिए कुछ नहीं मिलता। प्रधान मंत्री ने जोकहा, वह तो अखबार में देखा लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके प्रॉस एंड कॉन्स को पूरे देश को नहीं बताया कि वहां क्या हुआ है। कितना हमें मिलेगा? भारतवर्ष को क्या मिलने वाला है? कौन देश अपनी आमदनी का कितना हिस्सा भारतवर्ष को देने जा रहा है भारत की किस मद के विकास के लिए, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम हमें। देश को कोई कॉन्फिडेंस में लिए बगैर विदेश में जाकर किसी तरह के किसी समझौते में हस्ताक्षर करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि मार्केट प्लस है। सिर्फ मार्केट फोर्सेज गरीब देश के अंदर निर्माण नहीं कर सकती हैं, इसके लिए हमें गरीब देश के अंदर यह देखना पड़ेगा कि यहां पर गरीबों की जो आम चीजें हैं, उनके बारे में हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उनका जो खास मुद्दा था वह यही था और यह देश के लिए अच्छा है और हम चाहते हैं कि ये जो मार्केट है, उसके मुताबिक हम चलें।

श्रीमती कमला सिन्हा : मार्केट प्लस में हमारे देश की जो मिडिल क्लास के लोग हैं बीस करोड़, वे भी उसमें आएंगे और विदेश का सामान हम खुद दरवाजा खोलकर खरीदेंगे, यहां उनका सामान बिकेगा और हिंदुस्तान जो है, एक मार्केटिंग ग्राउंड होगा डेवलप्ड नेशन्स के लिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी **सरोज खापर्डे**) : कमला जी आपका टाइम हो गया।

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं दो मिनट में खत्म कर रही हूं। मेरे साथी टोका-टाकी कर रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : इसके बावजूद भी मैंने आपको काफी टाइम दिया।

श्रीमती कमला सिंहा : बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भारत वर्ष देश एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है, एक ऐसी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है इसका भी कोई अहसास सरकारी दल को नहीं है। इस देश के अनेक हिस्सों में एक तरफ तो इम्रजेंसी चल रही है, विदेशी ताकतों की घुसपैठ हो रही है, इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ देश के अन्दर बहुत बड़े हिस्से में ऐसी शक्ति उभर रही है जो यह चाहती है कि इस देश में धर्म निरपेक्षता न रहे। उन्हें किसी दूसरे धर्म के लिए टालरेंस नहीं है। वे लोग इस देश को केवल एक धर्म का देश, एक समुदाय का देश बनाकर रखना चाहते हैं। यह इस देश के लिए सबसे बड़ खतरे की घंटी है। भारत वर्ष ने हमेशा विश्वास किया वसुदेव कुटुम्बकम पर। जब सारी दुनिया को कुटम्ब मानते हैं तो हमारी धरती में जो लोग रहने वाले हैं उनको हम कुटुम्ब क्यों नहीं मान सकते। हमारे देश में एक ऐसी शक्ति पनप रही है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समय कांग्रेस आपस में झगडा कर रही है। उनके पैर के नीचे से ताकत खिसक रही है। लेकिन उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार में रहते हुए वह इन खतरों से बेखबर हैं। अपनी मौज मस्ती में अपना काम चलाय जा रही है। यह नहीं समझ रही है कि कंगुरे पर बैठ रहो लेकिन नींव की इंट खिसक रही है। यह देश बर्बाद न होने पाय। यह देश जीवित रहेगा तो आप और हम सब लोग जीवित रहेंगे। राष्ट्रपति जी ने अपने संदेश में इस बात को नहीं कहा है मुझ इस बांत का बहुत खेद है।

दूसरी आखिरी बात कह कर समाप्त करूंगी। मेरे पहले बोलने वाले नारायणसामी जी इस वक्त सदन में नहीं हैं। उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में शड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्ल्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत कल्याणकारी काम का जिक्र किया मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस देश की आबादी का लगभग 22 प्रतिशत शड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का है। उनके कल्याणकारी कामों के लिए सरकार ने कितना प्रावधान किया है यह मैं बताना चाहती हूं। द एस.सी., एस. टी फाईनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन हैज बीन स्टैप्डअप एंड इट हैज बीन अथोराइज्ड शेयर केपिटल फ्राम समीज 125 करोड़ टु 300 करोड़। जो समाज के सबसे शोषित और दलित लोग हैं, सबसे पीड़ित लोग हैं उनके कल्याण के लिए इतना ही प्रावधान किया है। इतना प्रावधान करके आपने बड़ी कृपा की। ठीक इसी तरह से नेशनल माइनोरिटी डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन एक बनाया गया।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप खत्म करिये।

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं खत्म कर रही रही हूं। हमारे देश में माइनोरिटी को अगर लिया जाए तो इसमें, मुसलमान, क्रिश्चन, सिख, पारसी, यहूदी सब आते हैं। लेकिन अगर मुसलमान को ही माइनोरिटी मान कर देखें तो इनकी आबादी करीब-करीब 16 करोड़ है। इसमें अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इनके लिए एक फाइनेन्शियल डवलपमेंट कार-पोरेशन जो बनाया गया इनकी शेयर कैपिटल दी है 500 करोड़ रुपये। इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी थोड़ी सी रकम आप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विकास इससे होगा। आप किसको भुलावा देना चाहते हैं ?

दुनिया अब काफी आगे बढ़ गयी है । लोग समझदार होने लगे हैं । इससे काम नहीं चलेगा । आपको थोड़ा उदार होना पड़ेगा । अगर आप सचमुच में सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो उनका उचित शेयर है वह उनको दे । You cannot have the whole cake? You will have to share it with others also.

महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में एक बात और कहना चाहती हूं । हमारा सरकार, जिसने यह वक्तव्य राष्ट्रपति द्वारा पढवाया है, उस सरकार को यह होश नहीं आया कि भारत वर्ष एक गांवों का देश हैं । इस देश में की आधी आबादी गांवों रहती है । उनमें से बहुत से लोगों ने दिल्ली नहीं देखी है; इस सदन को भी नहीं देखा । टेलीविजन भी उनके पास नहीं है । अगर उनके पास टेलीविजन होता तो वे टेलीविजन में भी देख सकते थे । मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है ? हम कोन से उपाय उनके लिए कर रहे हैं ? आप लोगों ने कहा कि यह तो प्रांतीय सरकारों का काम है । लेकिन प्रांतीय सरकारों को जो उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए, क्या उनको केन्द्र सरकार दे रही है ? जब तक केंन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को उनका उचित हिस्सा नहीं देगी तब तक प्रांतीय सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पायेगी । अगर ऐसा होगा तो इससे इस दश में एक ज्वालामुखी फटेगा, इस चेतावनी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam Vice-Chairperson, I rise to support the Motion moved by Shri Suresh Pachouri, expressing our gratitude to the President for delivering the Address. Madam, I was patiently hearing Mr. Mathur, an hon. Member of the House. He was very critical of the Government and was taking some kind of a satisfaction that there were certain bomb explosions. His first allegation was that the investments for the public sector are limited and more investment has come into the private sector. I am glad that they have accepted the fact that there are investments in the country. Whether it is the public sector or the private sector, there are investments. As far as the public sector is concerned, definitely the Government has a policy. Even people like us have defended the public sector, but we are not arguing for more public sector. Mr. Mathur was very enthusiastic about the public sector. I would like to know to what extent the Governments controlled by the BJP have gone in for the public sector. Naturally when they speak on the floor of the House, they are also responsible for running Governments in different States. I wish to know whether those Governments have any right to go in for the public sector and public sector investment.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Let us not discuss it here. That can be discussed in the concerned Assemblies.

SHRI VAYALAR RAVI: When you speak about public sector investment, you have to tell us what you have done in States where you are in power. I am sorry, you cannot quote any example or any instance from

the States where you are in power. But I accept the fact that the investment has gone up. That is one good sign.

Sir, the other thing is that the Sarkaria Commission was constituted in this country for going into the matter of sharing the powers between the Centre and the States....

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I am not sure whether the hon. Member is correct. The investment has gone down. If you look at the figures, you will find that it has gone down.

SHRI VAYALAR RAVI: I agree. I am not disputing anything. ...(*Interruptions*)... Yes, it has gone down, but now the Government is trying to protect the existing industries rather than going in for more public sector. Everyone knows that. I agree with that. I entirely agree with that. But my point is, as Mr. Mathur said, investment by the private sector has gone up. So, in totality, the investment has gone up.

DR. BIPLAB DASGUPTA: No, it is not so. If you look at the ratio of investment to GDP, it has gone down... (*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: I am not talking in terms of GDP. I am talking in real terms. ...(*Interruptions*)... Madam, I am talking in real terms. The questions is, now the State has more powers in regard to investments. The scenario has changed. Hon. Biplab Dasgupta also knows that his Party is also in power for the last seventeen or eighteen years in a State. Now, they gained power in West Bengal long back. Today the situation has very much changed. The entire scenario has changed and the economic situation has changed. Even the Sarkaria Commission has gone into the details to strengthen the relations. For the last three years the Government of India has taken up the policy of liberalisation. It has given more viability to every State Government. It has given more freedom to every State Government. Now, the development of the country has become a matter of correlation of the Centre and the States. It is not the monopoly of the Centre alone. It has become a matter correlation and understanding between the Centre and the States. Now, I cannot hear any clamour from the State Government for more power because there is no licence system. Every State Government is free to go in for its own investments and its own programmes. One hon. lady Member spoke about the investment in the power sector. In the last five years, who has prevented the Laloo Prasad Government to invest in the power sector in Bihar? Did we prevent it? Did anybody prevent it? They could have very well done it. Any public sector, any Government, any Electricity Board can go in foreign collaboration. Nobody is objecting to it. Even I appreciate it. The West Bengal Government had a quarrel with the Government of India. They invested in the power sector on their own. Mr. Jyoti Basu made a public confession because he wanted to invest in the power sector. What I am saying is that today the situation has changed. After the policy of liberalisation, the States have been given more powers or economic and industrial development. Now, it is more in the hands of the States. They can go ahead on their own. Nobody is standing in their way. Now, every political party is sharing the power. So, this is the changed political situation in this country. Every political party sitting on the other side is sharing the power. So, their contribution is also equally important for the development of the nation. I am not giving any sectarian view. I am only saying that the development can be done only through the joint effort of the Centre and the State. That is possible. So, the question today is whether other political parties have taken that responsibility. I am not questioning the sencerity of any political party ruling any State Gov-

ernment. But, when we speak of populist programmes—I am one for that—is there any political party which looks into the economic impact, the impact of that programme on its own State's autonomy? Can any State Government overdraft everyday, every month? Can any State Government blame the Centre for not overdrafting beyond the point? Madam, I want to make to a suggestion which the hon. Members should also consider. Let us think jointly of a programme which helps the poor. Mr. N. T. Rama Rao announced a Rs. 2/- a kg. rice scheme. I appreciate that. I can understand the message. But its impact is there. There can be any programme like that for the poor and the downtrodden people. For this we have to strengthen the Public Distribution System. There should be an understanding between the Centre and the States in this regard. It needs to be discussed in a wider forum including the National Development Council. The President also mentioned about the Public Distribution System. The Public Distribution System operates in two ways. The Public Distribution System is the only way through which the economic growth and development can reach the poor people, wether it is by way of subsidy or whatever it is. So, the PDS should be strengthened. This is the most importance factor. The Government of India alone cannot do it. The State Governments have also to play an important role in this regard. There should be some coordination between the Centre and the States to strengthen the PDS. Without strengthening it we cannot control the rise in prices. As Mr. Narayanasamy has pointed out, price rise is yet to be controlled. I am sorry to say so. But, it is not in the hand of the Centre alone. You go to the market. You will see that the prices have gone up. In the last three years the price of rice has gone up by 58 per cent and the prtce of wheat has gone up by 45 per cent. In Kerala the price of rice in the ration shops is more. You will be surprised to know that the price of rice in ration shops in Kerala is Rs. 6.20 a kg. In the open market the price was Rs. 6.50. Recently, it has gone up to Rs. 10. I asked some of the rich wholesalers, "Why did you increase the price of rice for Rs. 4 to Rs. 10?" "What happened?" They said that they were getting rice from Andhra Pradesh at Rs. 6 and Rs. 4. After the two rupee rice scheme was introduced in Andhra Pradesh, Mr. Rama Rao told the rice growers that they could increase the price of rice that was being sent outside the State. In fact, the people of Kerala are paying more because of the two rupee rice scheme in Andhra Pradesh. The local market price has gone up. We are paying more. Because of the States which have surplus rice and which have introduced certain schemes, the price in the local markets of other States has gone up. The other States are required to pay more and this is effecting the poor people. Hence, subsidy in the case of PDS should increase. By strengthening the PDS, we can control the price. The Government has to take strong measures in this respect. The Civil Supplies Department should raid the godowns of hoarders and arrest them. They should be put behind the bars. Otherwise, we will have to pay a heavy price. The poor people will have to suffer. In this connection, I would like to mention about a new scheme that we have introduced in Kerala. It is called the Mavelli store. I do not know if Mishraji is aware of the Mavelli store in Kerala. It is one of our major successful experiments. Above five to six items like rice, pulses, kerosene oil and salt are sold here at subsidised rates. In every village we have about three to four Mavelli stores. The State Government is subsidising it. I wish that the Central Government also shared the subsidy. It should encourage other State Governmnets to have similar schemes apart from the PDS.

We should have such parallel systems so as to help the poor. Some five or six items should be made available at cheap rates. This is the only way to control prices. The other thing that I would like to mention is the Centre-State relations. It is very important. The Centre-State relations are not cordial. For example in Gujarat, the BJP Government seized the NDDB godowns. I do not want to go into its merits.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I would like to know from you whether during this period of four years the poor people have become poorer or not. If you say that they have not become poor and we say that they have become poorer then why not ask an experts committee to go into the matter and tell us the truth? What is your opinion?

SHRI VAYALAR RAVI: The poverty line could not be brought down in spite of development. Even the Governmet statistics do not show that it has come down.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I want your assessment. Are the poor people becoming poorer or not?

SHRI VAYALAR RAVI: They are not becoming poorer. But their standard of living is not going.

SHRI CHATURANAN MISHRA: You have been asking the cooperation of all of us. Why not set up an experts committee to examine this question?

SHRI VAYALAR RAVI: I said that the Centre and the States should work jointly at the Government level for the advancement of the society.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I asked you whether the poor have become poorer or not.

SHRI VAYALAR RAVI: They have not become poor. Their standard of living may not have gone up as was expected. In the case of the upper strata of the society, it has gone up.

SHRI CHATURANAN MISHRA: That is not my point. Why are you talking about the upper strata. I am asking you about the lower strata. Have they not become poorer?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He has said that the rich have become richer.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Ravi is well aware of the fact that the per capita income in India was 370 dollars according to the UNDP report.

Now it has come down to 310 dollars. You can draw your own inferences from this.

SHRI JAGESH DESAI: That is not the picture.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, it is already 5.00 p.m. I think we should adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Ravi, one minute. I would like to take the sense of the House whether we should continue the discussion or adjourn the House till tomorrow.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Let us sit up to 6.00 p.m. and adjourn the House then. What is there? I am for continuing the debate till 6.00 p.m.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, you please adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I think the sense of the House is that we should adjourn the House. I adjourn the House till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th April, 1995.